• वर्ष-3

• अंक-287

रायपुर, गुरुवार 11 जुलाई 2024

• पृष्ठ-8

• मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› ज्योतिष में है भविष्य...

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति में केंद्रीय मंत्री खट्टर का राहुल पर तीखा वार

हिंदू हिंसक होते तो श्रीराम मंदिर बनने में 500 साल नही लगतेः खट्टर

रायपुर। केंद्रीय ऊर्जा, आवास व शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रायपुर में आयोजित भाजपा की वृहद प्रदेश कार्यसमिति में राहुल गांधी के हिंदू हिंसक होते है वाले बयान पर करारा प्रहार किया और कहा है हिंदू हिंसक होते तो, श्री राम मंदिर बनने में 500 साल नही लगते।श्री खट्टर ने कहा कि महज 99 सीटें जीतकर कांग्रेस भ्रामक आंकड़े पेश करके झूठ बोलकर अमर्यादित बाते कर रही है। खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस आज केंद्र की राजग सरकार को अल्पमत की सरकार बताकर झूठ बोल रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2004 और 2009 में यूपीए की सरकार में कांग्रेस ने क्रमशः 145 और 206 सीटें हासिल की थी जबकि यूपीए को 225 और 262 सीटें मिला थी। अल्पमत की इन सरकारों को थर्ड फ्रंट ने समर्थन दिया था।

जबकि आज एनडीए 293 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसमें भाजपा की 240 सीट हैं। श्री खट्टर ने बुधवार को यहां पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में प्रदेश भाजपा की विस्तारित कार्य समिति बैठक का उद्घाटन किया।

विस व लोस में भाजपा में कांग्रेस को चारों खाने चित्त कियाः देव

इससे पूर्व अपने प्रास्ताविक स्वागत भाषण में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 54 सीटों पर जीत हासिल की और लोकसभा में मत प्रतिशत बढ़कर 52.6 प्रतिशत मत लेकर 68 विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक बढ़त बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील करते हुए देव ने कहा कि प्रदेश और केंद्र में सरकार बनने के बाद अब अपने वचन जो पूरे किए जा रहे हैं उसे लेकर लोगों तक पहुंचना है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब निर्धारित कार्य योजना के क्रियान्वयन में सभी पदाधिकारी नेता कार्यकर्ता सहभागी बने। कुछ महीने बाद निकाय और पंचायत चुनाव में हमें शत प्रतिशत जीत हासिल के लक्ष्य को सामने रखना है।

जब तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारी सरकार न बने हमारा सफर अधूरा है:नितिन

कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति में हुई चर्चा और तय कार्य योजना को लेकर जन-जनतक जाना है। कांग्रेस शासन काल में भाजपा के आंदोलनों में जनता के मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने भाजपा को सत्ता तक पहुंचा है। कांग्रेस के खिलाफ हुए चरणबद्ध आंदोलन में कार्यकर्ताओं की सहभागिता ने भाजपा को जीत दिलाई है। लेकिन यह जीत अभी आधा सफर है। हम सरकार सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ही नहीं बनाते। अभी और आगे जाना है पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जब तक भाजपा का झंडा नहीं फहराएगा हमारा सफर अधूरा है। श्री नबीन ने कहा कि कांग्रेस के वोट बैंक को पूरी तरह घटाकर हमें बीजेपी को मजबूत बनाएंगे इसलिए हमें निकाय और पंचायत चुनाव में जीतने के लिए एकजुट होना है।

हमारी सरकार की योजनाएं ला रही बड़ा परिवर्तन : साय

रायपुर। हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कांग्रेस के समय में आबकारी में जो नियम बनाए गए थे जिसके कारण शराब घोटाला हुआ हमने उन नियमों को हटाकर नए नियम बना दिये ताकि भ्रष्टाचार का कोई स्रोत ही ना बचे। सारे ऑफलाइन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हम उन्हें ऑनलाइन कर रहे हैं। पिछले 5 साल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए उन सभी के दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो इस दिशा में भी हमारी सरकार मजबूती से कदम उठा रही है। सभी घोटालों की जांच हो रही है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला मामले में लोगों को डेढ़ साल से जमानत नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आप सभी को यह आश्वस्त करता हूं कि हम सभी पूरी निष्ठा के साथ जनहित में परिश्रम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, यह आप सभी को पता है, कांग्रेस ने प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया था, जनता त्रस्त थी। कांग्रेस ने जनता के बीच क्या क्या भ्रम फैला रखा था, यह आप सभी जानते ही हैं।

उस समय हमारे प्रदेश प्रभारी के रूप में आए ओम माथुर जी कहते थे कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। उनकी इस बात पर हम सभी सोच में पड़ जाते थे, कांग्रेस ने बहुत दुष्प्रचार जो किया था। आदरणीय शिव प्रकाश जी ने स्वयं एक-एक संभाग में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। अजय

छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री

जामवाल जी ने संगठन की गतिविधियों को मजबूती देने में अपना बहुत योगदान दिया। साय ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले 7 जुलाई 2023 को श्री नरेंद्र मोदी ने यहां आयोजित एक सभा में अउ नई सहिबो, बदल के रहिबो का आह्वान किया था इसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में वातावरण ही बदल गया।

आईआईटी छात्रों के प्लेसमेंट पैकेज में गिरावट को लेकर राहुल ने साधा निशाना

भाजपा की है शिक्षा विरोधी मानसिकता

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि देश के युवा बेरोजगारी से पूरी तरह हतोत्साहित हो गए हैं और दावा किया कि भाजपा की शिक्षा विरोधी मानसिकता के कारण उनका भविष्य अध्यक्ष में है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख की टिप्पणी एक मीडिया रिपोर्ट पर आई है, जिसमें दावा किया गया है कि 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) से स्नातक होने वाले इंजीनियरों के वेतन में नियुक्ति में मंदी के कारण गिरावट आई है। गांधी ने अपने व्हाट्सअप चैनल पर कहा कि आर्थिक मंदी का दुष्परिणाम अब देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी को भी भुगतना पड़ रहा है।

आईआईटी से प्लेसमेंट में लगातार गिरावट और वार्षिक पैकेज में गिरावट से युवाओं की हालत और खराब हो रही है, जो बेरोजगारी के चरम का सामना कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 2022 में 19% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल सका और यही दर इस साल दोगुनी होकर 38% हो गई। गांधी ने कहा कि जब देश के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का यह हाल है तो बाकी संस्थानों की क्या दुर्दशा होगी।

आज युवा बेरोजगारी से पूरी तरह हतोत्साहित है - माता-पिता पेशेवर शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं, जबकि छात्र उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। फिर नौकरी या सामान्य आय न मिलना ही उनकी वित्तीय स्थिति में गिरावट का कारण बन रहा है। गांधी ने कहा कि यह भाजपा की शिक्षा विरोधी मानसिकता का परिणाम है, जिसके कारण इस देश के मेधावी युवाओं का भविष्य अध्यक्ष में है। क्या मोदी सरकार के पास भारत के मेहनती युवाओं को इस संकट से मुक्त कराने की कोई योजना है? उसने पूछा। गांधी ने कहा, विपक्ष अपनी पूरी ताकत से युवाओं की आवाज उठाना जारी रखेगा और इस अन्याय के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराएगा।

नीट-यूजी 2024 पेपर लीक के आरोपों के संबंध में एनटीए का सुको में हलफनामा

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने बुधवार को नीट-यूजी 2024 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। गोधरा और पटना के कुछ स्थानों के केंद्रों पर व्यक्तियों से जुड़ी कथित कदाचार की घटनाओं के आलोक में एनटीए ने इन केंद्रों पर उपस्थित सभी उम्मीदवारों के प्रदर्शन का गहन मूल्यांकन किया। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या कदाचार की घटनाओं से कोई महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न हुआ है जिसके महत्वपूर्ण पैमाने के व्यापक परिणाम हो सकते हैं। एनटीए द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, उम्मीदवार के प्रदर्शन के डेटा विश्लेषण से पता चला कि कथित कदाचार ने पूरी परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया या गोधरा और पटना में उपरोक्त केंद्रों पर परीक्षा देने वाले छात्रों को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया। एनटीए का हलफनामा स्थिति की व्यापक समीक्षा का संकेत देता है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कथित कदाचार के बावजूद, हृश्वश्वज्ञ-त्र 2024 परीक्षा की समग्र पवित्रता बरकरार है, जिससे मामले पर स्पष्टता मिलती है। कथित परीक्षा पेपर लीक के कारण नीट-यूजी 2024 परीक्षा को दोबारा कराने की मांग के मामले में सुको का फैसला केंद्र की स्थिति से काफी प्रभावित होगा।

देश में डेंगू के बढ़ते मामलों पर केंद्र अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की बैठक

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश भर में डेंगू की स्थिति की समीक्षा करने और मानसून की शुरुआत और वृद्धि को देखते हुए डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को देश भर में डेंगू की स्थिति और मंत्रालय की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। यह बताया गया कि केंद्रित, समयबद्ध और सहयोगात्मक गतिविधियों के परिणामस्वरूप डेंगू मामले की मृत्यु दर 3.3% (1996) से घटकर 2024 में 0.1% हो गई है। मानसून की शुरुआत से उत्पन्न चुनौती और बरसात के मौसम के दौरान डेंगू के मामलों की संख्या बढ़ने के खतरे को रेखांकित करते हुए, नड्डा ने डेंगू के खिलाफ तैयार रहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू के खिलाफ रोकथाम, रोकथाम और प्रबंधन उपायों को मजबूत करने और मजबूत करने का निर्देश दिया। नड्डा ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे मुख्य रूप से उच्च बोझ वाले राज्यों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जहां अक्सर प्रकोप की सूचना मिलती है। उन्होंने अधिकारियों से डेंगू की रोकथाम पर ठोस परिणाम लाने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से काम करने का आग्रह किया।

प्रमुख समाचार

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान में शामिल होकर लोगों को करें जागरूक

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन से पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी माता जी के सम्मान में राजधानी रायपुर में दहीमन और गृह ग्राम बगिया में रुद्राक्ष का पौधा रोपा है। श्री साय ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि इस अभियान में अधिक से अधिक शामिल होकर छत्तीसगढ़ महतारी की गोद को हरा-भरा बनाने में अपना योगदान दें। राज्य शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया पर एक पेड़ माँ के नाम प्रोफाइल पिक्चर फ्रेम अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत आप अपने घर आँगन, खेत में अपनी माता जी के साथ या माता जी की स्मृति में पौधा लगाते हुए अपनी तस्वीर लें। इसके बाद अपनी तस्वीर के साथ एक पेड़ माँ के नाम प्रोफाइल पिक्चर फ्रेम लगाने के लिए दिए गये लिंक को क्लिक करें। इसके बाद प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड कर अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप/एक्स/फ़ेसबुक/इंस्टाग्राम/स्नैपचैट इत्यादि पर डिस्प्ले के रूप में लगायें।

छत्तीसगढ़ रोजगार एप्पः युवाओं को मिल रही है पंजीयन की सुविधा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर प्रदेश के युवाओं को घर बैठे रोजगार पंजीयन की सुविधा मिल रही है। साथ ही रोजगारपरक सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार एप्प का शुभारंभ किया है। एप्प शुभारंभ के महज तीन माह के भीतर ही इस रोजगार एप्प को 10 हजार लोगों ने डाउनलोड किया है। वहीं 1611 लोगों ने घर बैठे पंजीयन भी कराया है। इससे युवाओं को रोजगार कार्यालयों में जाकर लंबी-लंबी लाईन नहीं लगानी पड़ रही है। वहीं समय और पैसे का बचत भी हो रही है। इस एप्प को गूगल प्ले स्टोर और विभागीय वेबसाइट https://erojgar.cg.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। कोई भी व्यक्ति रोजगारपरक जानकारी के लिए एप्प डाउनलोड कर अवलोकन कर सकते हैं। गौरतलब है कि बेरोजगार युवाओं को मोबाइल एप्प के माध्यम से रोजगार हेतु पंजीयन की व्यवस्था, पहले से हो चुके पंजीयन का नवीनीकरण और नवीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ रोजगार एप्प विकसित किया गया है।

अयोध्या में बाहरी लोगों को जमीन बेची गईः अखिलेख

लखनऊ। समाजवादी पार्टी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को अयोध्या में बाहरी लोगों को जमीन की कथित बिक्री को लेकर भाजपा सरकार पर हमला किया और अरबों रुपये के भूमि घोटाले का दावा किया। उन्होंने इन भूमि सौदों की गहन जांच की भी मांग की। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि जैसे-जैसे अयोध्या की ज़मीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफ़ा कमाने के लिए बड़े स्तर पर ज़मीन की ख़रीद-फ़रोख़्त की है। सपा नेना ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 सालों से सर्किल रेट न बढ़ाना, स्थानीय लोगों के ख़िलाफ़ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपये के भूमि घोटाले हुए हैं। यहाँ आस्थावानों ने नहीं बल्कि भू-माफ़ियाओं ने ज़मीनें ख़रीदी हैं। उन्होंने कहा कि इन सबसे अयोध्या-फ़ैज़ाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहनेवालों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। ग़रीबों और किसानों से औने-पौने दाम पर ज़मीन लेना, एक तरह से ज़मीन हड़पना है। हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर हुई 'धांधली' और भूमि सौदों की गहन जाँच और समीक्षा की माँग करते हैं।

जम्मू में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की होगी पहचान

नई दिल्ली। पिछले 13 वर्षों से जम्मू-कश्मीर में रहने वाले अवैध विदेशियों की पहचान करने के लिए यूटी प्रशासन ने सात सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल उन अवैध विदेशियों की पहचान करेगा जो 2011 से अधिक समय से रह रहे हैं और उनके निर्वासन की सुविधा प्रदान करेगा। सात सदस्यीय पैनल को अवैध प्रवासियों की जीवनी और बायोमेट्रिक विवरण इकट्ठा करने और नियमित आधार पर एक अद्यतन डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने का काम सौंपा गया है। एक आदेश में सरकार के प्रमुख सचिव, गृह विभाग, चंद्राकर भारती ने कहा कि 2011 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। पैनल की अध्यक्षता गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव करेंगे। पैनल के अन्य सदस्यों में पंजाब के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, जम्मू और श्रीनगर मुख्यालय के आपराधिक जांच विभाग, और सभी जिला एसएसपी और एसपी, राज्य समन्वयक, एनआईसी के साथ शामिल हैं।

कपिल ने उपराष्ट्रपति के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि धनखड़ द्वारा सदन में विपक्ष के सदस्यों के संबोधन में लगातार व्यवधान डाला जा रहा है। सिब्बल ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले समेत कुछ मुख्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने यह भी दावा किया के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं में अयोध्या में जमीन खरीदी है। इसके अलावा सिब्बल ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। राज्यसभा सांसद ने कहा कि सदन में विपक्षी नेताओं के भाषणों को टीवी पर नहीं दिखाया जाता। उन्होंने कहा कि राज्यसभा अध्यक्ष बार बार विपक्ष के नेताओं के भाषणों में हस्तक्षेप करते हैं। जब धनखड़ कहते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। सिब्बल ने कहा, 'पीएम मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति अध्यक्ष हामिद अंसारी के काम करने के तरीके को लेकर गलत टिप्पणी की और यह ठीक नहीं है।

केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ में हो रहे कार्यों की समीक्षा की

राज्य और केन्द्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का होगा तेजी से विकास : खट्टर

छत्तीसगढ़ जल्दी ही वापस पाएगा 'पॉवर सरप्लस स्टेट' का दर्जाः साय

रायपुर। केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में ऊर्जा तथा शहरों में आवास व जनसुविधाएं विकसित करने किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक सुधारवादी कदम उठाएं जा रहे हैं। जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में कहा कि लोगों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने केन्द्र सरकार द्वारा अनेक अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं हैं। उन्होंने राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दी जा रही सभी निधियों और अनुदानों का पूर्ण उपयोग करने को कहा। राज्य में जिस तेजी से काम होंगे, उसी तेजी से भारत सरकार द्वारा राशि जारी की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में विकास योजनाओं को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से कोई कठिनाई नही आएगी। दोनों बेहतर समन्वय से काम करेंगे। केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में सुझाव दिया कि क्लिीन सिटी के तहत रायपुर को मिली 100 बसों का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच चलाने के लिए भी कर सकते हैं। उन्होंने विद्युत विभाग के अंतर्गत लाइन-लॉस को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बिजली उत्पादन के लिए कोयला की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्यों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बैठक में केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि कार्यभार सम्भालने के एक माह के भीतर ही वे यहां विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उनके सहयोग से राज्य में विकास की गति को तेज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल्दी ही 'पॉवर सरप्लस स्टेट' का दर्जा वापस पा लेगा। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश में पिछले छह महीनों में किसानों और छोटे कामगारों के लिए बिजली की उपलब्धता में सुधार आया है। किसानों को तीन एचपी तक कि सिंचाई पंपों में सालाना छह हजार यूनिट तक और तीन से पांच एचपी के पंपों में साढ़े सात हजार यूनिट तक के बिजली बिल में छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृति के लिए लंबित 19 हजार 906 आवास एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में एकत्रित आवेदनों के अनुरूप राज्य को पुनरीक्षित केन्द्रांश के साथ करीब 50 हजार आवासों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज की यह बैठक राज्य में ऊर्जा और शहरी विकास को नई गति प्रदान करेगी।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरूण साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हम लगातार काम कर रहे हैं। राज्य में स्वच्छता, आवास, आजीविका, पेयजल इत्यादि के लिए तेजी से काम हो रहे हैं। इन कार्यों में प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार के सहयोग से इन कार्यों में आगे और भी तेजी आएगी।

चार नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने किया गिरफ्तार

सुकमा। सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत जगरगुण्डा क्षेत्र से चार नक्सलियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार सभी नक्सली थाना चिंतलनार क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। नक्सलियों को गिरफ्तार करने में जिला बल, डीआरजी एवं बस्तर फाइटर जिला सुकमा की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है।

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी किरण चौहान ने बताया कि नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत मुखबिर के आसूचना के आधार पर माओवादियों का पता-तलाश जारी रखते हुए मुखबिर की सूचना पर संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन एवं नक्सली आरोपियों की धरपकड़ हेतु ग्राम मिलमपल्ली व आस-पास क्षेत्र की ओर रवाना हुए कि अभियान के दौरान जगरगुण्डा के आंगनबाड़ी भवन के पाास सादे वेश-भूषा धारण किये कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा

पुलिस पार्टी को अपने ओर आते हुए देखकर भागने/छिपने लगे, जिनमें से घेराबंदी कर 04 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया।

पकड़े गये संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना नाम कमशः 01. पोटाम भीमा पिता पाण्डू उम्र लगभग 35 वर्ष जाति मुरिया निवासी एर्रापारा सुरपनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा, 02. मड़कम राजु पिता सुकड़ा उम्र 35 वर्ष जाति मुरिया निवासी नीलापारा सुरपनगुड़ा थाना चिंतलनार सुकमा, 03. मड़कम सन्ना पिता मड़कम नंदा उम्र 22 वर्ष जाति मुरिया निवासी इंगारपारा सुरपनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा एवं 04. सुण्डाम भीमा पिता लखमा उम्र 25 वर्ष निवासी एर्रापारा सुरपनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा का होना तथा सभी नक्सल संगठन में सुरपनगुड़ा आरपीसी अंतर्गत मिलिशिया सदस्य के पद पर कार्य करना बताया।

पकड़े गये संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा रखे गये थैले की चेकिंग करने से क्रमशः- 01. पोटाम भीमा पिता पाण्डू के कब्जे के थैला से 02 नग जिलेटिन राड, 20 मीटर कोर्डेक्स वायर, नक्सल साहित्य, 02. मड़कम राजू पिता सुकड़ा के कब्जे के थैला से 0 ह्लष्4 नग डेटोनेटर, लगभग 30 मीटर इलेक्ट्रिक वायर, 02 नग पेंसिल सेल 03. मड़कम सन्ना के कब्जे से पॉलिथिन में बारूद लगभग 100 ग्राम 05 नग डेटोनेटर 02 नग पेंसिल सेल, 04 सुण्डाम भीमा पिता लखमा के कब्जे से एक पॉलिथिन 02 नग टॉप टाईगर बम, 02 नग जिलेटिन रॉड, लगभग 10 मीटर इलेक्ट्रिक वायर, माचिस, बमरामद किया गया। उपरोक्त सामाग्री को रखे जाने के संबंध में गहन पूछताछ करने पर बताये कि बड़े नक्सलियों के कहने पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से रखना एवं कुदेड़ के पास सुरक्षाबलों के पार्टी को नुकसान पहुचाने की नीयत प्लांट करने की घटना में शामिल रहना जो पुलिस पार्टी को देख भाग गये थे।

उक्त कृत्य विधि विरुद्ध पाये जाने से थाना जगरगुण्डा में अपराध क्रमांक 12/2024 धारा 04, 05, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत् पंजीबद्ध प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

मॉनसून में एंटी नक्सल ऑपरेशन ने छीना नक्सलियों का चैन

कांकेर। छत्तीसगढ़ में मॉनसून का सीजन नक्सलियों को लिए सबसे आरामदायक माना जाता था। क्योंकि नक्सली ये मानते थे कि बारिश के समय में जंगल के अंदर आकर फोर्स का ऑपरेशन करना नामुमकिन है। लेकिन वक्त बदला तो नक्सलियों के खिलाफ बनने वाली रणनीति भी बदली।इसकी एक ताजा तस्वीर मंगलवार को देखने को मिली। जब घने जंगलों के बीच से जवानों का वीडियो सामने आया। जवानों ने भरी बारिश के बीच बीनागंडा के जंगल में नक्सल ऑपरेशन चलाकर इनामी महिला नक्सली को ढेर किया।इस दौरान तेज बारिश ने प्यासे जवानों की प्यास भी बुझाई। जैसे बारिश ये कह रही हो कि आईए आपके हौंसलों को हम यूं ही सलाम करते हैं।

डीआरजी के जवानों ने मंगलवार सुबह छोटेबेठिया थाना के बीनागंडा इलाके में एक महिला नक्सली को मार गिराया। इस ऑपरेशन के लिए जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान एंटी नक्सल आपरेशन में निकले जवानों की तस्वीर सामने आई। जहां जवान बारिश के पानी को पालीथिन से इकट्ठा करके पी रहे हैं। वही जब जवान वापस लौट रहे हैं तो नाला उफान में होने के कारण जवानों को काफी दिक्कत आई। इसके बाद भी जवानों ने महिला नक्सली के शव को अपने कंधों में उठाया और उफनते नाले को मार किया। आपको बता दें कि

बरसात में बीनागुंडा तक पहुंचना काफी मुश्किल था।नदी नाले में पानी अचानक बढ़ जाता है, वर्तमान में हो रही बारिश से जंगल के रास्ते में इतना ज्यादा कीचड़ है कि वहां चलना काफी मुश्किल है। वह भी स्वयं को सुरक्षित रखते हुए। जवान सुरक्षित तरीके से चलते हुए 12 किमी दूर सोमवार शाम तक लगातार चलते हुए नक्सलियों के कैंप से महज डेढ़ किमी पहले तक पहुंच गए। अंधेरा होने के कारण वे रात में जंगल में रुके।इसके बाद उजाला होने का इंतजार करने लगे। मंगलवार सुबह उजाला होते ही जवान फिर से धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे।इसके बाद नक्सलियों के कैंप को घेर लिया। जवानों को करीब आता देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने मोर्चा लेकर जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से करीब एक घंटे तक फायरिंग हुई। नक्सलियों के ओर से फायरिंग जब रुकी तो जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जिसमें एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ। इसके साथ ही घटनास्थल से एक नग 303 रायफल, एक नग 315 बोर रायफल सहित भारी मात्रा में हथियार और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई। इसके बाद जवान महिला नक्सली का शव लेकर वापस लौटे।

20 पार्सल बोगियों को लीज पर लेने के लिए टेंडर जारी

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेलवे बिलासपुर ने 10 ट्रेनों के 20 पार्सल बोगियों (एसएलआर) के पट्टे के लिए ई-टेंडर जारी किया है और इसे आईआरईपीएस वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पट्टा आवंटन प्रक्रिया 19 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे शुरू होगी. सभी इच्छुक व्यक्ति जिनके पास डिजिटल हस्ताक्षर यानी डीएससी है, इस ई-बोली में भाग ले सकते हैं।

बिलासपुर डिविजनल कोरबासी वासपुर-इंदौर आसपुर चित्र रिवेरा इंदौर आसपुर रीव आसपुर रीव आसपुर रीव एयरासपुर डोरस्पासपी, 182एसपी, 18114 बिलासपुर - टी अटागरगरगर एक्सप्रेस, 17481 ससपुर-तिरुपति ससपुर ग्रेग्रेस, 11209 शहडोल- 20 पार्सल को लीज पर देने के लिए ई-टेंडर जारी किया गया है कोच नागपुर एक्सप्रेस, 22407 अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस और 18239 कोरबा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस सहित 10 ट्रेनों में। पट्टा धारक को वाहन के प्रारंभिक स्टेशन के साथ-साथ मार्ग के सभी पार्सल-आधारित स्टेशनों पर पार्सल लोड करने और उतारने की सुविधा होगी।

नक्सली करने लगे लैब का उपयोग, कांकेर एनकाउंटर में हुआ खुलासा, पुलिस भी हैरान

कांकेर। कांकेर में मंगलवार को छोटेबेटियां थाना क्षेत्र के विनागुंडा गांव के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई जिसमें एक के महिला नक्सली ढेर हुई। महिला नक्सली से हथियार के साथ-साथ पहली बार मुठभेड़ स्थल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने निकल कर आई है। दरअसल नक्सली अपने सुरक्षित ठिकाने पर प्रयोगशाला यानी लैब बनाये हुए थे जिसे जवानों ने ध्वस्त कर दिया साथ ही लैब के सामानों को अपने साथ ले आए।

नक्सलियों के लैब से भारी मात्रा में प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले सामान बरामद हुआ है। नक्सलियों के लैब से सूक्ष्मदर्शी, नाइट्रिक एसिड, थर्मोमीटर, टेस्ट

ट्यूब, ट्रांजिस्टर, वर्नियर कैलीपर्स सहित कई भौतिक और रसायन विज्ञान लैब में उपयोग होने वाले समाग्रीयां और एक अंग्रेजी में लिखा हुआ विज्ञान की किताब के पन्ने मौके से बरामद हुआ हैं। पहली बार जंगल में नक्सलियों के ठिकाने से इस प्रकार से लैब के समान मिलाना कई सारे सवालों को जन्म जरूर दे रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच रही है।

इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज एनकाउंटर के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया गया है. फोर्स का मानना है कि इलाके में अभी और नक्सली छिपे हो सकते हैं। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए फोर्स जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है. साल 2024 में अबतक हुए मुठभेड़ों में 139 नक्सली मारे गए हैं. एनकाउंटर में ढेर हुए 139 नक्सिलयों में से अकेले 137 नक्सली बस्तर में ढेर हुए हैं. जबकी दो नक्सली धमतरी जिले में मारे गए है।

बैंक में काम करने वाले लिपिक ने किया 2 करोड़ का घोटाला

■ **बलौदाबाजार सहकारी बैंक का क्रिमिनल क्लर्क, मृत लोगों के खाते से रुपये करता था गायब**

बलौदाबाजार। केंद्रीय सहकारी बैंक बलौदा बाजार शाखा में 2 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने वाले क्लर्क को तीन साल कठोर कारावास की सजा मिली है। सजा के साथ ही कोर्ट ने 22 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि भी जमा करने को कहा है।

सहायक लोक अभियोजक अमित बाजपेयी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया आरोपी का नाम सूरज साहू है। जो बलौदाबाजार के इंद्रा कॉलोनी का रहने वाला है। केंद्रीय सहकारी बैंक बलौदा बाजार शाखा में लिपिक के पद पर पदस्थ था। अपनी पदस्थापना के दौरान 45 साल के आरोपी क्लर्क ने सहकारी बैंक में जमा राशि में बड़ा घोटाला किया। आरोपी ने 22 लाख 55 हजार 149 रुपये का घोटाला किया। इसके अलावा वटगन बैंक शाखा में आरोपी सूरज साहू ने सहायक लेखापाल होते हुए 2 करोड़ से ज्यादा का घपला किया था। जिसका मामला पलारी थाने में दर्ज किया गया। बैंक में गबन के खुलासे के बाद जांच दल का गठन किया गया। बैंक स्कैम कोतवाली थाना में आईपीसी की धारा 409 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

अमित बाजपेयी
सहायक लोक अभियोजक

इस मामले की सुनवाई 6 जुलाई को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलौदा बाजार मंजू लता सिन्हा की कोर्ट में हुई। जज ने आरोपी सूरज साहू को 3 साल का कारावास और 22 लाख 55 हजार 149 रुपये क्षतिपूर्ति राशि जमा करने का दंड दिया।

आरोपी लेखापाल ने अपने ही बैंक की उपभोक्ता मृत बैसाखिन बाई गेंडरे के खाता क्रमांक 624046114649 से 13 मई 2022 को एक लाख और एक माह बाद 14 जून 2022 को 4900 रुपए निकाले। जिसका मैसेज जब घर के मोबाइल पर गया तो परिजन इसकी जानकारी लेने बैंक पहुंचे। शाखा प्रबंधक को फोन में आए बैंक के मैसेज को दिखाते हुए बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। घर के किसी भी सदस्य ने उनके खाते से पैसे नहीं निकाले, फिर उनके खाते में ट्रांजेक्शन कैसे हुआ। मैसेज को देखकर शाखा प्रबंधक ने इसकी जांच की तो उनके ही बैंक के लेखापाल सूरज साहू द्वारा राशि निकालने की पुष्टि हुई। जिसके बाद राशि तत्काल उपभोक्ता के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया। इस पर सूरज ने अधिकारी को गुमराह करते हुए वापस बैंक के दूसरे खाते से उपभोक्ता के खाते में पैसा डाल दिया। जब इस बात की जानकारी प्रबंधक को हुई तो उन्होंने बैंक के दूसरे खाते की प्रारंभिक जांच कराई। जिसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई। जिसके बाद इसकी सूचना मुख्यालय को दी गई। इस मामले में जांच टीम बिठाई गई। जिसमें खुलासा हुआ कि आरोपी सहायक लेखापाल ने चार साल में बैंक को लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है।

सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने से किया मना

मरीज से की अभद्रता, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन का आयोजन किया गया है। जनदर्शन में कलेक्टर रणबीर शर्मा ने लोगों से वन-टू-वन चर्चा की। जनदर्शन में जिले भर से 32 आवेदकों ने अपनी समस्या, मांग और शिकायत से संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए।

इस दौरान बेमेतरा तहसील क्षेत्र के ग्राम खाम्ही निवासी राधेलाल निषाद ने उपस्वास्थ्य केन्द्र मरका में प्रसव कराने में मना करने व अभद्र व्यवहार करने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके व मरीज के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

इसी प्रकार ग्राम बड़गड़ा निवासी संतोष लोधी ने अपने कृषि भूमि पर दूसरे द्वारा किया कब्जा हटाने के संबंध में आवेदन दिया। बेरला तहसील के ग्राम खर्रा निवासी राम वर्मा ने ऑनलाइन भूमि रिकार्ड सुधार करवाने, ग्राम लेंजवारा के सभी पंच ने विकास कार्यों में हो रहे घोटाले और भ्रष्टाचार के संबंध में आवेदन दिया।

नवागढ़ तहसील के ग्राम अंधियारखोर के ग्रामीणों ने पुलिया व नाली से अतिक्रमण हटाने, पानी निकासी की व्यवस्था कराने, साजा तहसील के ग्राम परसबोड़ निवासी भागवत घृतलहरे ने चार माह मजदूरी भुगतान दिलाये जाने के संबंध में आवेदन किया है। जनदर्शन में कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को गौर से सुना व संबंधित अधिकारियों से फोन पर व कई को समक्ष बुलाकर संबंधित आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। कुछ आवेदन का मौके पर निराकरण किया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सरकारी राशन को बेचते रंगे हाथों पकड़ाया दुकान संचालक

सक्ती। पीडीएस चावल की अफरा तफरी करते खाद्य विभाग के अधिकारियों ने दुकान संचालक को रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक, पीडीएस दुकान संचालक सरकारी राशन को व्यापारी को बेच रहा था। आज तड़के सुबह व्यापारी की पिकअप में सरकारी चावल लोड करा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही एसडीएम सहित खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। सक्ती में महामाया महिला स्व सहायता समूह के नाम से पीडीएस दुकान संचालित है। दुकान संचालक लंबे समय से पीडीएस चावल की अफरा तफरी कर रहा था। गरीबों के चावल को व्यापारियों को बेचा करता था।

वृद्धा सुमृता बाई को हर माह मिलेगा निःशुल्क राशन

कोरबा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव ने कहा कि उन्होंने आम जनता के राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं के आवेदनों का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया है। यही कारण है कि प्रशासन की कोशिश है कि राशन कार्ड के लिए आवेदकों के आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए. ऐसे आवेदन सार्वजनिक डोमेन में हैं और उनका त्वरित समाधान किया जा रहा है। सुमृता बाई के अंत्योदय राशन कार्ड के आवेदन पर भी त्वरित कार्यवाही की गई। कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड की ग्राम पंचायत सुमरिता बाई ने कलेक्टर के समक्ष आवेदन लगाया। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने तत्काल खाद्य अधिकारी को सुमृता बाई को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिये। आवेदन भरने के बाद सुमृता बाई के नाम से अंत्योदय राशन कार्ड जारी किया गया और ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से घर तक पहुंचाया गया। इसी प्रकार ग्राम जोरहाडबरी विकासखण्ड पाली निवासी श्री प्रवीण कुमार ने अपनी माता के नाम से जारी राशन कार्ड से अपना नाम हटाने हेतु स्वेच्छा से सार्वजनिक रूप से आवेदन किया।

लंबे समय से अनुपस्थित तीन शिक्षक और कर्मचारी बर्खास्त

खैरागढ़। लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। 3 शिक्षकों और एक कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है। इसमें शासकीय प्राथमिक शाला

पांडुका के सहायक शिक्षक संजय कुमार ध्रुव, शासकीय प्राथमिक शाला करेला के सहायक शिक्षक महेंद्र वर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुढ़ीपार के सहायक ग्रेड 3 भूपेंद्र सिंह बैंस और शासकीय प्राथमिक शाला हीरावाही की सहायक शिक्षिका सीमा अग्रवाल शामिल हैं। बता दें कि बीते दिनों कलेक्टर ने साप्ताहिक बैठक में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई थी। इसके बाद जनपद पंचायत सीईओ ने आदेश जारी कर दो शिक्षकों को बर्खास्त किया था। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने दो कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।

मोटरसायकल अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई

बालोद। रानीमाई मंदिर मोड़ के पास तेज रफ्तार मोटरसायकल अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, इस हादसे में दुर्ग जिला के ग्राम विनायकपुर (अंडा) निवासी तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक नमन सेन पिता राज सेन का सगा भाई डेविड सेन तथा एक अन्य बालिका अलग मोटर सायकिल में सवार थी जबकि दूसरे मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 बीसी 0145 में नमन के साथ देवानंद पिता हंसराज निषाद तथा खिलेश पटेल जिले के प्रमुख तीर्थस्थल सियादेवी मंदिर दर्शन को आए हुए थे। वापस गृहग्राम जाते समय रानीमाई मंदिर मोड़ में अनियंत्रित होकर नमन का मोटर सायकिल पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में नमन सेन, देवानंद निषाद तथा खिलेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही संजीवनी 108 की टीम पहुंची और शव का पंचनामा करने के बाद तीनों शव को जिला अस्पताल लाया गया गया पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

अहाता की नीलामी से 13.80 लाख के राजस्व की हुई प्राप्ति

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर छत्तीसगढ़ के सभी अंग्रेजी शराब दुकानों के अहाते के लिए निविदा निकाली गई थी जिसमें बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तीन अंग्रेजी शराब दुकानों 13 लाख 80 हजार रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई। सबसे ऊंची बोली राजपुर अंग्रेजी शराब की दुकान की लगी तो वही सबसे कम बोली छत्तीसगढ़ के सीमा पर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान रामानुजगंज के लिए लगी। गौरतलब की छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा के द्वारा शराब की बिक्री के साथ-साथ अंग्रेजी शराब दुकान के आसपास आहाता के लिए टेंडर निकाला गया था। यह टेंडर पूरे प्रदेश में एक साथ निकाला गया। अलग-अलग अंग्रेजी शराब दुकान के लिए अलग-अलग बोली लगी। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के अंग्रेजी शराब दुकान राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज वाड्रफनगर, कुसमी के लिए प्रदेश स्तर में तीन बार टेंडर निकाला गया। तब जाकर तीन अंग्रेजी शराब दुकान राजपुर, कुसमी एवं रामानुजगंज के लिए बोली लग सकी।

धान सूखत होने पर कलेक्टर का एक्शन, समिति प्रबंधक और डाटा ऑपरेटर्स पर गिरी गाज

बेमेतरा। बेमेतरा जिला में वर्ष 2023- 2024 के धान खरीदी केंद्र में धान के उठाव कार्य में गड़बड़ी के मामले में तीन समिति प्रबंधक समेत तीन ऑपरेटर पर कार्रवाई हुई है। समिति प्रबंधक और ऑपरेटर्स को बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने निलंबित कर दिया है। गौरलतब हैं कि बेमेतरा जिला में पिछले साल बड़ी तादात में धान खरीदी हुई थी। लेकिन धान के उठाव का काम काफी धीमा हुआ। जिसके बाद खुले में रखा धान प्रभावित हुआ था।खुले में रखे धान में सुखत आ गई थी। जिसे लेकर अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरु की है।

बेमेतरा जिला के धान खरीदी केन्द्र मोहगांव में कुल 9161 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। जिसमें कुल 9055 मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। वहीं 106 मीट्रिक टन कमी आ गई। वहीं शेष धान का निराकरण समिति प्रबंधक संस्था के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ने नहीं किया। जो खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के धान खरीदी नीति की कंडिका क्रमांक

16.9 का उल्लंघन में आता है। शासन को हुई आर्थिक क्षति को देखते हुए दिगम्बर राजपूत समिति प्रबंधक मोहगांव और संस्था के डाटा एंट्री ऑपरेटर नितिन साहू को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है।

वहीं धान खरीदी केन्द्र साजा में कुल 6668 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। जिसमें कुल 6630 मीट्रिक टन का उठाव होने के बाद कुल 38 मीट्रिक टन कमी हुई। बचे धान का निराकरण समिति प्रबंधक और संस्था के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ने यहां भी नहीं किया। जिसके बाद समिति प्रबंधक दीपक सोनी और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर शरद वैष्णव को निलंबित किया गया है।

अमृत मिशन का नगर पंचायतों में हाल-बेहाल

■ **टेंडर में लाखों खर्च, लेकिन काम नहीं हुआ शुरू**

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। एमसीबी जिले के तीनों नगर पंचायत खोंगापानी,नई लेदरी और झगराखांड में घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के मकसद से एक साल पहले अमृत मिशन योजना को स्वीकृति मिली थी। स्वीकृति मिलने के बाद अब तक एक साल में 9 बार टेंडर कॉल किया गया। काम तो चालू नहीं हो पाया लेकिन टेंडर कॉल में ही छत्तीसगढ़ सरकार का पचास लाख से अधिक का खर्च हो चुका है। इधर इन तीनों नगर पंचायतों में आम जनता शुद्ध पेयजल के लिए तरस रही है।

नगर पंचायत के कई वार्डों के लोग प्राकृतिक जलस्त्रोतों से पानी इकट्ठा करके पी रहे हैं।कई जगह पर निस्तारी वाले गंदे और बदबूदार पानी को ही छानकर लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। नगर पंचायत लेदरी की बात करें तो सबसे अधिक समस्या वार्ड नंबर 6,7 और 13 वार्ड नंबर में है। जहां सुबह से पानी के लिए बच्चों सहित पूरा परिवार जद्दोजहद करता हैं। आलम ये है कि यहां के निवासियों को दो किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। इस

बारे में पहले नगर पंचायत के सीएमओ को इस बारे में जानकारी दी गई।लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। नगर पंचायत नई लेदरी की अध्यक्ष सरोज पांडेय ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या विकराल होती जा रही है।लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। अभी तक पानी के लिए हम पूरी तरह एसईसीएल पर निर्भर हैं। एसईसीएल भी पूरे नगर पंचायत में पानी सप्लाई नहीं देता है। ये हाल सिर्फ नई लेदरी नगर पंचायत का ही नहीं है। बल्कि खोंगापानी नगर पंचायत का भी है।वार्ड नंबर 13 के पार्षद कमलभान चौधरी ने वार्ड में पानी की समस्या को माना।पार्षद की माने तो पाइप लाइन का विस्तार भी कराया गया है। लेकिन नगर पंचायत की उदासीनता के कारण पाइपलाइन चालू नहीं हो सकी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जगदीश मधुकर ने कहा कि कई बार इस संबंध में नगर पंचायत को बोला गया लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में मनेंद्रगढ़ विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि जल्द समस्या दूर होगी।

कैबिनेट मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा दूरस्थ क्षेत्र और नियम में कठोरता के कारण कार्य में देरी हो रही है। अमृत मिशन का कार्य जल्द पूरा होगा। संबंधित विभाग से बातचीत कर जल्द कार्य कराने पहल की जाएगी।

इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्र की योजना को अब तक शुरु ही नहीं किया जा सका है।जबकि लाखों रुपए टेंडर निकालने के नाम पर खर्च हो चुके हैं।ऐसे में यदि कोई ठेकेदार काम करने के लिए आगे नहीं आएगा तो अमृत मिशन का जल कभी भी जरुरतमंदों तक नहीं पहुंचेगा।

राज्य और केन्द्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का होगा तेजी से विकास: खट्टर

केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने छत्तीसगढ़ में हो रहे कार्यों की समीक्षा की, छत्तीसगढ़ जल्दी ही वापस पाएगा 'पॉवर सरप्लस स्टेट' का दर्जा : साय

रायपुर। केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में ऊर्जा तथा शहरों में आवास व जनसुविधाएं विकसित करने किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक सुधारवादी कदम उठाएं जा रहे हैं। जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने बैठक में कहा कि लोगों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने केन्द्र सरकार द्वारा अनेक अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं हैं। उन्होंने राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दी जा रही सभी निधियों और अनुदानों का पूर्ण उपयोग करने को कहा। राज्य में जिस तेजी से काम होंगे, उसी तेजी से भारत सरकार द्वारा राशि जारी की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में विकास योजनाओं को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से कोई कठिनाई नही आएगी। दोनों बेहतर समन्वय से काम करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने बैठक में सुझाव दिया कि क्लिीन सिटी के तहत रायपुर को मिली 100 बसों का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच चलाने के लिए भी कर सकते हैं। उन्होंने विद्युत विभाग के अंतर्गत लाइन-लॉस को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बिजली उत्पादन के लिए कोयला की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्यों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बैठक में केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि कार्यभार सम्भालने के एक माह के भीतर ही वे यहां विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उनके सहयोग से राज्य में विकास की गति को तेज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल्दी ही 'पॉवर सरप्लस स्टेट' का दर्जा वापस पा लेगा। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश में पिछले छह महीनों में किसानों और छोटे कामगारों के लिए बिजली की उपलब्धता में सुधार आया है। किसानों को तीन एचपी तक कि सिंचाई पंपों में सालाना छह हजार यूनिट तक और तीन से पांच एचपी के पंपों में साढ़े सात हजार यूनिट तक के बिजली बिल में छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृति के लिए लंबित 19 हजार 906 आवास एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में एकत्रित आवेदनों के अनुरूप राज्य को पुनरीक्षित केन्द्रांश के साथ करीब 50 हजार आवासों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज की यह बैठक राज्य में ऊर्जा और शहरी विकास को नई गति प्रदान करेगी।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरूण साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हम लगातार काम कर रहे हैं। राज्य में स्वच्छता, आवास, आजीविका, पेयजल इत्यादि के लिए तेजी से काम हो रहे हैं। इन कार्यों में प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार के सहयोग से इन कार्यों में आगे और भी तेजी आएगी। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुश्री रूपा मिश्रा, विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री शशांक मिश्रा, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की निदेशक सुश्री अनिता मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक श्री कुंदन कुमार, क्रेडा के सीईओ श्री राजेश सिंह राणा और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक श्री प्रदीप्ता कुमार मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

संक्षिप्त समाचार

कोर्ट ने रानू साहू की जमानत याचिका खारिज की

रायपुर। कोल लेवी घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इससे पहले मंगलवार को रानू की जमानत याचिका पर रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद जज ने बुधवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

डोंगरगढ़ नपा में आया अविश्वास प्रस्ताव प्रमोद दुबे व आशीष पर्यवेक्षक नियुक्त

रायपुर। नगर पालिका परिषद, डोंगरगढ़ के अध्यक्ष के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा एवं नगर निगम रायपुर के सभापति प्रमोद दुबे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। नियुक्त पर्यवेक्षकद्वय नगर पालिका डोंगरगढ़ का दौरा कर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ बैठक कर स्थानीय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं पार्टी संगठन के निर्वाचित पार्षदों के साथ समन्वय स्थापित कर 12 जुलाई 2024 को प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव के विरुध्द मतदान बनाने की दिशा में समुचित कार्यवाही करेंगे। उक्त आदेश प्रभारी महामंत्री (संगठन एवं प्रशा.) मलकीत सिंह गैदू ने जारी किया है।

सीएम साय और मनोहरलाल खट्टर ने महेंद्र सिंह कलचुरी की शोक सभा में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने आज राजधानी रायपुर के गौरव गार्डन में आयोजित स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह कलचुरी की शोकसभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री साय और केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने शोक संतप्त परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। उल्लेखनीय है कि श्री महेंद्र सिंह कलचुरी का देहावसान 27 जून को हुआ था। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव, केंद्रीय राज्यमंत्री आवास एवं शहरी मामले श्री तोखन साहू, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल सहित परिवारजन उपस्थित रहे।

रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव

बैज के सामने ढेबर समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, मांगी टिकट

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को कांग्रेस में माहौल गरमाने लगा है। अभी तक चुनाव तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस में टिकट पाने शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में उपचुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक शुरू होने से पहले ही राजीव भवन प्रत्याशी बनाने के नारे से गूंज उठा।

दरअसल, पहली बैठक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की थी। बैठक समाप्त सभी वरिष्ठ नेता कांग्रेस भवन से रवाना हो गए। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। पत्रकारों से चर्चा कर वे जैसे ही दूसरी बैठक के लिए जाने लगे, ढेबर समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। समर्थकों ने बैज के सामने नारेबाजी करते हुए रायपुर दक्षिण से एजाज ढेबर को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने की मांग की।

बता दे कि रायपुर दक्षिण से कांग्रेस से कई नेताओं की ओर से दावेदारी करने की खबर है। जिसमें महापौर, सभापति सहित कुछ पार्षद के नाम भी शामिल हैं बताए जा रहे है।

सीईओ ने दो ग्राम पंचायत सचिवों को थामाया नोटिस

- पंचायत कार्य में लापरवाही बरतने का है मामला

तखतपुर। जिला पंचायत सीईओ ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले तखतपुर ब्लॉक के दो ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसमें बहतराई ग्राम पंचायत के सचिव लालजी कौशिक और ग्राम पंचायत साल्हेकापा के सचिव सुखनंदन सिंगरोल को नोटिस जारी किया गया है।

जिला पंचायत सीईओ ने कहा है कि छग राज्य ग्रामीण क्षेत्र और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के विकास प्राधिकरण अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 6 लाख रुपये की राशि सामुदायिक भवन निर्माण के लिए दी गई थी। यह काम आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। सीईओ ने तीन दिन के भीतर निर्माण कार्य का वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ उपस्थित होकर जवाब देने कहा है। इसी तरह तखतपुर क्षेत्र के साल्हेकापा के ग्राम पंचायत के सचिव सुखनंदन राठौर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसमें कहा गया है कि 5 साल पहले सांस्कृतिक मंच के निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये की राशि स्वीकृत थी। यह काम आज तक पूरा नहीं हो सका है। इन दोनों सचिवों के खिलाफ पंचायत कार्य में लापरवाही की शिकायत लगतार मिल रही थी। जिसे जिला पंचायत सीईओ ने गंभीरता से लेते हुए अब नोटिस जारी किया है।

राज्यपाल हरिचंदन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किया पौधरोपण

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन आज राजभवन में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती पद्मावती देवी की याद में आम का पौधा लगाया।

श्री हरिचंदन ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा कि पौधरोपण करना सभी के लिए जरूरी है। पूरे विश्व को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। वातावरण का प्रदूषण देश एवं दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है विशेषकर कोविड महामारी के बाद इससे खतरा और बढ़ गया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदूषण सभी बीमारियों की जड़ है। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए समाज, देश एवं विश्व के वातावरण को प्रदूषण से बचाना होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देश में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान शुरू कर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया है।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार श्री भीष्म प्रसाद पांण्डेय, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री श्रीनिवास राव एवं राजभवन के सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में लोगों का फूटा गुस्सा, रामा उद्योग के विस्तारीकरण का किया विरोध

धरसींवा। औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा के सीएसआईडीसी कार्यालय परिसर में रामा उधोग के विस्तारीकरण की पर्यावरणीय जनसुनवाई मंगलवार को हुई। आसपास की ग्राम पंचायतों में मुनादी नहीं होने के कारण अधिकांश ग्रामीण जनसुनवाई में शामिल नहीं हो सके। लेकिन जो कहीं से सूचना मिलते ही पहुंचे तो उन्होंने भी विस्तारीकरण का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों के अलावा कुछ जनप्रतिनिधियों, श्रमिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण के बीच समुचित प्रचार-प्रसार किये बिना इस तरह जनसुनवाई पर सवाल खड़े किए और रामा उद्योग के विस्तारीकरण का विरोध किया।

रामा उद्योग के विस्तारीकरण का जिन इक्का दुक्का लोगों ने समर्थन किया उनमें से विस्तारीकरण का समर्थन करने वाले एक व्यक्ति से जब न्यूज़ 24 की टीम ने सवाल किया तो उसने बताया कि वह रामा उधोग में काम करता है।

वहीं जनसुनवाई के दौरान रामा उद्योग के केमिकल युक्त पानी से परेशान किसान कोमल पाल ने अपनी धान की फसल की बर्बादी की पीड़ा सुनाई और विस्तारीकरण का विरोध किया। जनसुनवाई में अधिकांश लोगों ने बढ़ते प्रदूषण और शोषण के चलते अपना विरोध दर्ज कराकर समुचित प्रचार-प्रसार के बाद ही जनसुनवाई रखने की बात कही। हालांकि जनसुनवाई में विस्तारीकरण का जमकर विरोध होने के बाद जब फेक्टरी प्रबंधन की ओर से मौजूद कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि रामा उद्योग के इस विस्तारीकरण से प्रदूषण बढ़ेगा नहीं बल्कि पहले से भी बहुत कम होगा।

एनएसयूआई-युकां कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने की डीजीपी से मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा को लेकर सियासी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में अब तक 150 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सलाखों के पीछे हैं। इसे लेकर कांग्रेस स्थानीय प्रशासन और भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों की गिरफ्तारी पर पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं के इशारे पर पुलिस कांग्रेस के लोगों की गिरफ्तारी कर रही है।

बलौदाबाजार हिंसा मामले में प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने डीजीपी से मुलाकात की है। इसके साथ ही हिंसा को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। घटना और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात की है। बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में कई एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक को नोटिस जारी कर थाना बुलाया जा रहा है। मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेताओं ने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन कम कर रही है। कांग्रेस संगठन के समर्थक निर्दोष पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और सतनामी समाज के लोगों जबरन गिरफ्तार कर रही है। इस घटना पर रोक लगाया जाए। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन अपनी सफलता को छुपाने के लिए निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। उनका आरोप है कि विपक्ष राजनीतिक दलों के साथ बदले की भावना के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मामले में एसआई विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा और यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने यह सवाल उठाया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक धनेंद्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, फूलोदेवी नेताम, सुबोध हरितवाल, राजेंद्र तिवारी, देवेंद्र यादव शामिल थे।

भाजपा कार्यसमिति की बैठक, शिवरतन शर्मा ने रखा राजनीतिक प्रस्ताव

कांग्रेस पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप, नगरीय निकाय चुनाव में जुटने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान

रायपुर। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आज हुई, जिसमें भाजपा उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि एक तरफ जहां भाजपा विश्वास और विकास के एक नए युग में भारतीय लोकतंत्र को ले जा रही है, वहीं कांग्रेस लगातार अपनी हरकतों से देश और लोकतंत्र को कलंकित कर रही है। कार्यसमिति ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भी जनता के बीच जाकर पार्टी की रीति-नीति, मोदीजी की गारंटी और अपनी सरकारों की उपलब्धियों को बताएं और निकाय व पंचायत चुनाव में भी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं।

राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में हिन्दुओं को हिंसक कहकर देश और सनातन समाज का अपमान किया है। इसी तरह उन्होंने श्रीराम मंदिर आंदोलन के के बारे में भी अनर्गल बयानबाजी कर हिंदू भावना को आहत किया है। यह विस्तारित कार्यसमिति राहुल गांधी के इस बयान की निंदा करती है। हजारों वर्षों से शांति और अहिंसा के लिए विख्यात हिन्दू समाज

को इस तरह अपमानित करने की जितनी निंदा की जाए वह कम है।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी लगातार झूठों का महाजाल फैलाया था। संविधान पर झूठ, आरक्षण खत्म कर देने का झूठ, चावल बंद कर देने का झूठ, महतारी वंदन योजना समाप्त कर देने का झूठ, यहां तक झूठ कि मोदीजी जीतेंगे तो आगे से चुनाव नहीं होंगे। इन तमाम झूठों का पर्दाफाश कर भाजपा ने सतत जनता का विश्वास हासिल किया है। हाल के दोनों चुनावों में मिली सफलता से उत्साहित यह कार्यसमिति भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करती है कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भी जनता के बीच जाकर पार्टी की रीति-नीति, मोदीजी की गारंटी और अपनी सरकारों की उपलब्धियों को लेकर निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं।

प्रदेश भाजपा की यह विस्तारित कार्यसमिति ऐसे महत्वपूर्ण और विलक्षण समय पर हो रही है, जब भाजपा ने चतुर्दिक विकास की ऐतिहासिक गाथा लिखी है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने सफलता की ऐसी कहानी लिखी है, जिसे दुहराना अन्य दलों के लिए सदियों में संभव नहीं होगा। आज इस कार्यसमिति को न केवल तीसरी बार पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने की प्रसन्नता है, बल्कि छत्तीसगढ़ समेत तीन बड़े राज्यों में भी ऐतिहासिक वापसी का गौरव भी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी तक की सबसे अधिक सीटें प्राप्त होने, अभी तक का सबसे अधिक मत प्रतिशत पाने और विपक्षी दल से मत प्रतिशत में सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल करने यह कार्यसमिति आह्लादित है। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ से 11 में से 10 सीट देकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दुहराने का भी संतोष यह कार्यसमिति व्यक्त करती है। भाजपा आज भरोसे का दूसरा नाम है। आज अनुछेद 370 और 35 ए बीते दिनों की बात हो गई है। बिना रक्त का एक कतरा बहे इस अनुच्छेद को निष्प्रभावी कर दिया गया। इसी तरह अयोध्या में श्रीरामलला आज अपने भव्यतम मंदिर में विराजमान हैं। त्वरित तीन तलाक को समाप्त कर भाजपा ने समान नागरिक आचार संहिता के वादे को भी लगभग पूरा करते हुए मोदीजी ने अपने दूसरे कार्यकाल में एक ही साथ सभी कोर मुद्दे का समाधान कर दिया है। जनता, कार्यकर्ता और नेता के बीच विश्वास बहाली का इससे बड़ा उदाहरण विश्व की राजनीति में भी शायद अन्य कोई नहीं होगा। पार्टी के सभी सांस्कृतिक मुद्दों को हल करते रहकर भी मोदीजी ने विकास और गरीब कल्याण को भी अपनी शीर्ष प्राथमिकता बनाए रखा देश से चाहे 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात हो या 80 करोड़ से अधिक लोगों तक लगातार नि:शुल्क अनाज पहुंचाने की, करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना से मुफ्त चिकित्सा की बात हो या चार करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास की, प्रदेश के हर घर तक बिजली पहुंचाने की बात हो या हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने की, सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, अस्पताल आदि की व्यवस्था करते हुए भी देश को विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने, और फिर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर चलने वाले हमारे प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे लोकप्रिय और मजबूत नेता बनकर सामने आए हैं। इन तमाम उपलब्धियों पर इस कार्यसमिति को गर्व है।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, धमतरी
जिला- धमतरी (छ.ग.)

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eprocuremnet Portal: https://eproc.cgstate.gov.in
(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्रमांक 155699/ नि. सूचना क्र. 01/वलेलि/2024-25, धमतरी, दिनांक 08.07.2024

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 29.07.2024 समय 17.30 तक ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है-

कार्य का नाम- ग्राम- सिरसिदा (रावनसिंघी) स्टापडेम कम काजवे के डाउन स्ट्रीम में दांयी तट पर आर.डी. 0 मी. से 45 मी. तक एवं बांयी तट पर आर.डी. 0 मी. से 45 मी. तट संरक्षण बंड का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत- रूपये 47.46 लाख (दिनांक 01.08.2010 के एस.ओ.आर. तथा संशोधित 22.08.2022 के अनुसार)

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 15.07.2024 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते हैं।

नोट- निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग धमतरी
जिला- धमतरी (छ.ग.)

जी- 242500965/6

वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं दल

योगेन्द्र योगी

राजनीतिक दलों का पूरा प्रयास रहता है कि वोट बैंक एकजुट रहना चाहिए, इसके लिए बेशक तमाम कायदे-कानून और नैतिकता को ताक पर क्यों न रखना पड़े। इसका नया उदाहरण तमिलनाडु की डी.एम.के. की सरकार ने दिया है। वोट बैंक की खातिर मुख्यमंत्री स्टालिन की सरकार ने पिछले दिनों तमिलनाडु में अवैध जहरीली शराब पीने से मरने वालों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा तक कर डाली। जनहित याचिका के जरिए यह मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि गैर-कानूनी काम करने वालों को इतना ज्यादा मुआवजा किस आधार पर देने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने कहा कि दुर्घटना के मामले में मुआवजा दिया जा सकता है किन्तु अवैध शराब से मौत के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। याचिका में कहा गया कि मजे के लिए अवैध शराब पीकर मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देना उन्हें ऐसे गैर-कानूनी कामों के लिए प्रोत्साहित करना है। जहरीली शराब से मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी या समाज सेवक नहीं थे, इन्होंने अपनी जान आम लोगों के भले के लिए नहीं दी, बल्कि अपने मजे लेने के कारण उनकी मौत हुई है। अदालत ने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर पुर्नविचार करना चाहिए। आश्चर्य यह कि स्टालिन सरकार से गठजोड़ करने वाली कांग्रेस ने इस पर एक बार भी आपत्ति नहीं जताई। तमिलनाडु विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ए.आई.ए.डी.एम.के. के सदस्यों ने कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड के मुद्दे को लेकर सवाल किए थे। इसके कारण पहले इन सदस्यों को एक दिन के लिए निलंबित किया गया था लेकिन अगले दिन हंगामे की स्थिति उत्पन्न होने के कारण उनको विधानसभा के पूरे सत्र से ही निलंबित कर दिया गया। स्टालिन सरकार की सहयोगी इंडिया गठबंधन की प्रमुख घटक कांग्रेस इस पर भी चुप्पी साधे रही। यह वही कांग्रेस है जिसने मणिपुर ङ्क्षहसा के मुद्दे पर संसद ठप्प करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। संसद की कार्रवाई में गतिरोध उत्पन्न करने के कारण विपक्षी दल के 140 सांसदों को निष्कासन झेलना पड़ा था। इस पर विपक्ष ने खूब शोर-शराबा मचाया था। निष्कासन को लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बताया गया। यह दोहरा मानदंड साबित करता है कि राजनीतिक दलों का स्वार्थ सिर्फ सत्ता तक सीमित है। राजनीतिक दल दिखावे के लिए ही लोगों की भलाई का दंभ भरते हैं। हकीकत यह है कि उन्हें वोट बैंक से मतलब है, इसके लिए बेशक किसी की जान जाए, खराब प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले या देश का नुकसान हो। सत्ता प्राप्ति के इस खेल में हर तरह का समझौता शामिल है, बस यह एहसास होना चाहिए कि वोट बैंक का फायदा मिल सकता है। सत्ता के लिए ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। इसका दूसरा बड़ा और निर्लज्ज उदाहरण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान देखने को मिला था। मुख्यमंत्री अखिलेश की सरकार ने टाडा के आतंकियों से मुकद्दमा इसलिए वापस ले लिया कि इससे अल्पसंख्यकों के वोट को रिझाया जा सके। देश तोडऩे वाली इस हरकत पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को तो मानो सांप सूंघ गया था। सबकी नजरें अल्पसंख्यकों के वोट बैंक पर लगी हुई थीं। राजनीतिक दल सरेआम इस तरह की देशद्रोही हरकत भी कर सकते हैं, बशर्ते सत्ता में आने के लिए वोट मिलने चाहिएं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर था। सरेआम माफियाओं का बोलबाला था। दोनों ही दल माफियाओं को मंत्री तक बनाने में भी पीछे नहीं रहे। राजनीतिक दलों की माफियाओं से नजदीकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा प्रमुख अखिलेश फातिहा तक पढऩे चले गए।

रूस से क्या लेकर लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी

शशिधर पाठक

भारत की बड़ी रक्षा जरूरतों में बस दो हैं, पहली भारतीय वायु सेना में पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान और दूसरी एस-400 ट्रायंफ जैसी प्रतिरक्षी मिसाइल प्रणाली की कम से कम 5 और यूनिट। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ पूर्व एयर वाइस मार्शल नरेन्द्र बहादुर सिंह कहते हैं कि इनके सैन्य बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की बड़ी सैन्य चिंता दूर हो जाएगी। दरअसल, भारत के पड़ोसी देश चीन के सैन्य बेड़े में जे-20 पांचवी पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान उड़ान भर रहा है। पाकिस्तान ने अपने सैन्य बेड़े के लिए इसे लेने की घोषणा दी है। क्षेत्रीय सामरिक सैन्य संतुलन के लिहाज से भारत को इस श्रेणी के लड़ाकू विमान(सुखोई-57) की जरूरत है। देखना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस मास्को यात्रा में इस पर कौन सा भरोसा मिलता है।

भारत के पास अभी सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में बहुउद्देश्यीय राफेल है। राफेल चौथी और पांचवी पीढ़ी के बीच का लड़ाकू विमान है। इसके बाद सुखोई-30एमके आई है। सुखोई-30 एमकेआई चौथी पीढ़ी के आस-पास का है। बताते चलें कि रूस और भारत से काफी पहले मिलकर पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने और इसकी तकनीक को साझा करने पर सहमति बना रखी है।

अमेरिका की लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने एफ-35 लाइटनिंग को विकसित कर रखा है। यह बहुउद्देश्यी, रेडार की पकड़ में न आने वाला, अद्वितीय मैनुअरिंग क्षमता से युक्त फाइटर जेट है। 2010 में ही संवाददाता ने मारिएट के आसमान में इसे उड़ान भरते देखा है। इसके अलावा का एफ-22 रैप्टर है। इन दोनों लड़ाकू विमानों को अमेरिका ने अपनी वायुसेना में शामिल किया है। ये ट्विन इंजन फाइटर जेट हैं। इसके अलावा एकल इंजन के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को विकसित करने में अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिक लगे हैं।

चीन की वायु सेना में चेंगदू जे-20 उड़ान भर रहा है। जे-20 भी पांचवीं पीढ़ी का ट्विन इंजन मल्टीरोल फाइटरजेट है। अत्याधुनिक सुविधाओं और मारक क्षमताओं से लैस है। चीन के रक्षा वैज्ञानिक भी एकल इंजन के फाइटर जेट को विकसित करने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हाल में अपनी वायुसेना में चीन के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को शामिल करने की घोषणा है।

अमेरिका के समानांतर ही रूस की वायुसेना में भी सुखोई-57 फेलॉन पर नाटो देशों की नजर है। हाल में युक्रेन ने रूस के हैंगर के पास ड्रोन हमले में सुखोई-57 को नष्ट करने का दावा किया था। माना जाता है कि सुखोई-57 फेलॉन दुनिया अत्याधुनिक, बहुउद्देश्यीय, लजवाब मैनुअरिंग क्षमताओं से युक्त घातक लड़ाकू विमान है। रूस इसके अगले संस्करण के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर भी काम कर रहा है और एकल इंजन के फाइटर जेट को विकसित करने की कोशिश जारी है।

दुश्मन को चकमा देना, रेडार और सर्विलांस की पकड़ में न आना, दुश्मन के ठिकानों की सटीकता से पहचान और पलक झपकने से पहले ही हाई स्पीड मानुअरिंग के साथ ओझल हो जाना। ऐसे फाइटर जेट जिसमें आक्रमण के साथ-साथ बचाव की क्षमता, देर तक उड़ान भरने, हवा में ईंधन लेने में सक्षम हो और एक फाइटर ही जेट से जमीन, हवा, जल तीनों क्षेत्र में युद्ध की डिजाइन और मांग को काफी हद तक पूरा किया जा सके। अपने अत्याधुनिक एलटीआर रेडार प्रणाली, एवियानिक्स, हेड माऊंटेड कॉकपिड, पायलट फ्रेंडली आपरेशन के सहारे हर संभावित लक्ष्य को साधने में संभव होते हैं।

पाकिस्तान, चीन से मिल रही चुनौतियों और क्षेत्रीय सामरिक संतुलन के लिए एस-400 ट्रायंफ और सुखोई-57 फेलॉन जैसे लड़ाकू विमान जरूरी हैं। एस-400 मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली है और यह दुश्मान के मिसाइल, राकेट, फाइटर जेट समेत तमाम घातक फ्लाइंग आब्जेक्ट हवा में दूर स्वत÷ पहचान कर काफी दूर(400-600 किमी) ही मार गिराने में सक्षम है। आंतरिक और वाह्य दोनों ही वायुमंडल से आने वाले खतरे को नेस्तनाबूत कर देती है। भारत के पास अभी इसकी तीन ईकाई है। सौदे के मुताबिक दो ईकाई रूस से आनी है और भारत इसकी कुछ और यूनिट चाहता है। इसे इस्राइल की मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली आयरन डोम और अमेरिका के पैट्रियट और इसके उन्नत संस्करणों की तरह काफी बेहतर माना जाता है। अभी तक भारत के पास कोई बहुत उन्नत और इसके आस-पास की मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है। प्रतिरक्षा प्रमाली में भारत के पास अभी आकाश मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली ही है और इसकी क्षमता तुलना में सीमित है।

एस-400 की तरह ही भारत को पांचवीं पीढ़ी का उन्नत लड़ाकू विमान भी चाहिए। ताकि चीन और पाकिस्तान की सैन्य ताकत को देखते हुए सामरिक सैन्य संतुलन बना रहे। भारतीय वायुसेना को दुनिया की मारक, घातक वायुसेनाओं में गिना जाता है। ऐसे सुखोई-57 लड़ाकू विमान के बेड़े में शामिल होने के बाद दुश्मन को भी किसी युद्ध जैसी संभावना के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा।

भारत और रूस के बीच में एक दशक से पहले ही संयुक्त प्रयास से पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने पर सहमति बनी थी। इसे हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की विमान निर्माता कंपनी के सहयोग से तैयार किए जाने पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी। लेकिन अभी भारत को कम से कम दो स्क्वाड्रान(एक स्क्वाड्रान में 16 फाइटर जेट और 2 प्रशिक्षण फाइटर जेट) चाहिए। रूस की तरफ से इसको लेकर प्रस्ताव आए थे लेकिन अभी दोनों देशों के बीच में इस पर कोई सहमति या सौदा नहीं हुआ है।

भारत ने रूस के साथ 2018 में एस-400 वायुरक्षा प्रणाली की पांच यूनिट लेने के लिए 5.4 अरब डालर का करार किया था। अक्टूबर 2023 तक रूस ने भारत को इसकी तीन प्रणालियां दे दी हैं। अभी दो प्रणालियों को रूस से प्राप्त किया जाना बाकी है। भारत चाहता है कि दोनों यूनिट उसे यथाशीघ्र मिल जाए। माना जा रहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण इसकी आपूर्ति में देरी हो रही है।

उम्मीद की जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता में मुद्दा उठाएंगे। दोनों देशों के बीच में इस मामले में सहमति बनने के भी पूरे आसार हैं। हालांकि भारतीय रक्षा वैज्ञानिक पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास और एस-400 जैसी प्रतिरक्षी मिसाइल प्रणाली को विकसित करने पर काम कर रहे हैं। बताते चलें कि चीन जैसे देश नहीं चाहते कि भारत को रूस से पांच यूनिट से अधिक एस-400 मिसाइल प्रतिरक्षा प्रमाली और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान मिलें। भारत के पास वर्तमान में अपनी नि दोनों रक्षा जरूरत को पूरा करने के लिए दो ही विकल्प हैं। एक रूस और दूसरा अमेरिका। अमेरिका की रक्षा मशीन और उत्पाद रूस की तुलना में तीन से चार गुणा तक मंहगी पड़ती है। दूसरे सोर्स कोड जैसे तमाम गतिरोध हैं। ऐसे में भारत के लिए सबसे उपयुक्त, विश्वसनीय सामरिक साझीदार सहयोगी देश रूस ही है।

पुराण दिग्दर्शन ....

पुराण-परिचयाध्याय (भाग-3)

गतांक से आगे...

पुराण- शब्द, पुरा अव्ययपूर्वक णीलृ (प्रापणे) धातु से ड प्रत्यय करने पर बनता है। पुरानी ड यह तीनों भाग व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार पुराण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अथवा पुरा अव्यय से पुराभव (पहले होने वाला) अर्थ में ट्यू प्रत्यय हो जाने पर सिद्ध हो जाता है।

पाणिनीय व्याकरण में - (क) सायं चिरं प्राह्णे प्रोऽव्ययेभ्यष्ट्यु ट्यू लौ तुट् च (4।3।22) (ख) पूर्वकालैकसर्थजरत्पुराण नवकेवला: समानाधिकरणेन। (2।1।46) (ग) पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु (4।3।105) (घ) युवोरनाको (ङ) अट् कुप्वानुव्यवायेऽपि (8।4।2) यह पाँच सूत्र पुराण शब्द की सिद्धि में काम आते हैं। शास्त्र विशेषण होने के कारण यह शब्द नपुंसक लिंग प्रयुक्त हुवा है।

निरुक्तकार यास्काचार्य ने अपने परम प्रसिद्ध वेदाङ्गभूत निरुक्त ग्रन्थ में पुराण शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया है -पुराणं कस्मात् - पुरा नवं भवति । (निरुक्त 3।16।24)

अर्थात् - पुराण क्यों कहा जाता है? इसलिये कि- जो कभी पहिले नया हो, यानी वर्तमान समय में जिसकी नवीनता अभीष्ट न हो। सीधे शब्दों में पुराने को पुराण कहा जाता है। प्राय: सभी कोशकार एक स्वर से इस अर्थ को स्वीकार करते हैं। प्रतन, प्रत्न, पुरातन, चिरन्तन इसके पर्यायवाची शब्द हैं, परन्तु पुराण शब्द विशेष रूप से अष्टादश ग्रन्थों में रूढ़-सा सो गया है। इसलिए अमरकोश (1।6।5) में- पुराणं पंचलक्षणम्। अर्थात् (1) सृष्टि की उत्पत्ति, (2) विनाश, (3) वंशपरम्परा, मनुओं का वर्णन तथा (5) विशिष्ट व्यक्तियों के चरित्र - यह पाव विषय जिन ग्रन्थों में मुख्यतया वणित हों उन्हें पुराण कहते हैं- ऐसा लिखा है।

क्रमश: ...

विश्व जनसंख्या दिवस

रमेश सर्राफ धमोरा

जनसंख्या से तात्पर्य एक सीमित क्षेत्र मे रहने वाले व्यक्तियो की संख्या से है। जब किसी क्षेत्र मे रहने वाले व्यक्तियो की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते है। अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे पता चलेगा कि किसी स्थान की जनसंख्या अधिक है। इसका उत्तर भी साफ है कि जब किसी क्षेत्र के युवाओ के लिए आमदनी के साधन कम हो जाये या किसी परिवार को अपनी दो वक्त की रोटी के लिए अत्याधिक परिश्रम करना पड़े तो निश्चित ही वहा की जनसंख्या आवश्यकता से अधिक होने लगी है।

हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल ने 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। इसके अगले साल 1990 में पहली बार दुनिया के 90 देशों में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जैसे परिवार नियोजन का महत्व, लैंगिक समानता, गरीबी पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन का सुझाव डॉ. के.सी.जकारिया ने दिया था। जब उन्होंने विश्व बैंक में सीनियर डेमोग्राफर के रूप में काम किया था। तब जनसंख्या पांच अरब तक पहुंच गई थी।

बढ़ती मानव जनसंख्या ने पूरी दुनिया के तंत्र को गहरे से प्रभावित किया और संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पैदा किया है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि-

अति रूपेण वै सीता चाति गर्वेण रावण:।
अतिदानाद् बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत।।

अर्थात् अति हर चीज की बुरी होती है। जिस तेजी से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। उसको देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब गणित के आंकड़े कम पड़ जाएंगे। क्योंकि धरती पर तो इतनी भूमि बचेगी नहीं कि इंसान रह सके। आज बेहिसाब बढ़ती जनसंख्या ना केवल चिंता का कारण है बल्कि सभी समस्याओं का मूल कारण भी है। फिर चाहे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ना हो, बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या संसाधनों का अभाव हो। बढ़ती जनसंख्या न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारे देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या के चलते बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे देश का विकास भी बाधित हो रहा है। सरकार के जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए नागरिकों को प्रेरित करने के प्रयास भी बहुत ज्यादा सफल होते नहीं दिख रहे। आये दिन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके पीछे देश में अन्धविश्वास और साक्षरता की कमी को जिम्मेदार मान सकते हैं। हम देश में ये मानने वाली सोच को जिम्मेदार मान सकते हैं जो कहती है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज्यादा कमाने वाले होंगे। जो लोग आज भी ऐसी सोच रखते हैं उन्हें ये समझना होगा कि सिर्फ घर में बहुत ज्यादा सदस्य होने से ही घर में आय नहीं बढ़ेगी। बल्कि इससे सभी के लिए भरण पोषण हेतु भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

सवालों के घेरे में बाइडेन की उम्मीदवारी

जे. सुशील

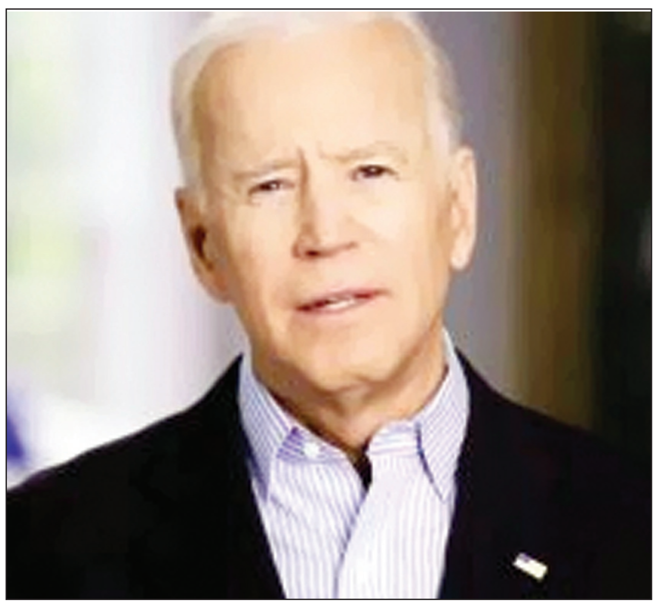

अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से जो बाइडेन के हटने या हटाये जाने की चर्चाएं जोरों पर है। बाइडेन लगातार कह रहे हैं कि वे दौड़ में बने हुए हैं और वे ही डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकते हैं। उनके मित्र और हवाई के गवर्नर जॉस ग्रीन ने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि अगर बाइडेन चुनाव नहीं लड़ते, तो वे यह काम उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंपेंगे।

ओबामा प्रशासन में अधिकारी रह चुके मीडिया कमेंटेटर वैन जोंस ने कहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बंद कमरों में यह चर्चा नहीं हो रही है कि बाइडेन को हटाया जाए या नहीं, बल्कि चर्चा यह हो रही है कि ऐसा कब किया जाए। अगर बाइडेन अपनी उम्मीदवारी छोड़ते हैं, तो यह पहली बार होगा कि एक प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद किसी पार्टी ने उम्मीदवार बदला हो। अगर बाइडेन ही उम्मीदवार रहे, तो यह पहली बार होगा कि दोनों दलों के उम्मीदवार- डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन- 75 साल से ऊपर के होंगे।

इससे पहले रोनाल्ड रीगन 69 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे और 77 साल की उम्र में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। बाइडेन 81 साल के हैं और ट्रंप 78 के। कुल अमेरिकी आबादी के 65 प्रतिशत हिस्से की उम्र 15 से 65 साल के बीच है और 65 साल से अधिक की आबादी 17 प्रतिशत है। उम्र के लिहाज से देखें, तो भी दोनों उम्मीदवार कहीं से भी प्रतिनिधि नहीं हैं। अमेरिका में औसतन 50-55 साल की उम्र में लोग राष्ट्रपति बने हैं, जिसमें उलिसस ग्रांट, जॉन कैनेडी, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा आदि कुछ राष्ट्रपति अपवाद रहे हैं, जो अपनी उम्र के 40वें दशक में राष्ट्रपति रहे। क्लिंटन 43 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे और अब वो 77 के हैं यानी ट्रंप और बाइडेन से छोटे।

हालांकि उम्र को अनुभव से जोड़ कर देखा जाता है, पर मसला सिर्फ अनुभव का नहीं है। पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाइडेन के बोलने, चलने और उनकी भाव-भंगिमाओं को देखकर लगता है कि अब वे अकेले न तो चल पाने में सक्षम हैं और न ही फैसले करने में। टीवी पर हुई प्रेसिडेंशियल बहस में लोगों ने देखा कि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। न्यूयॉर्कर के संपादक डेविड रेमनिक ने मार्क ट्वेन को उद्धृत करते हुए लिखा है कि हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है और बिखरना है, लेकिन बाइडेन दुनिया के सामने टीवी पर बिखर रहे हैं। बाइडेन को भी पता है कि वे बूढ़े हो चुके हैं, पर शायद सत्ता की चाह ऐसी ही होती है। डेमोक्रेट तबकों में भी मांग उठ रही है कि बाइडेन खुद ही पीछे हटें ताकि किसी नये उम्मीदवार को मौका मिले। अभी पार्टी सम्मेलन बाकी है और तकनीकी रूप से नया उम्मीदवार आ सकता है। उनकी उम्मीदवारी को लेकर बहुत समय से शंका जाहिर की जाती रही है। उनके बेटे हंटर बाइडेन को सजा सुनाये जाने के बाद भी पार्टी का एक तबका चिंतित था कि चुनाव में क्या होगा। पर अब मामला उम्र पर चला गया है, जिससे बाइडेन की रेटिंग खराब होती जा रही है।

लेकिन ऐसा क्या है कि पहले अमेरिका में उम्मीदवार अमूमन 50-60 के बीच हुआ करते थे, वहीं अब मामला 70 से अधिक के उम्मीदवारों पर आ गया है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, मसलन युवाओं की राष्ट्रीय राजनीति में घटती दिलचस्पी, लोगों का पैसा और समृद्धि जुटाने पर फोकस तथा यथास्थिति कायम रखने की कॉरपोरेट नीति। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी युवा राजनीति नहीं समझता है। ध्यान रहे कि पिछले दिनों ही बड़ी यूनिवर्सिटियों में गाजा को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। पर राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के अलावा युवाओं की राजनीतिक भागीदारी कम दिखती है क्योंकि उन्हें पता है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि उनके पास खूब पैसा हो।

यह पैसा हर तरह के चुनाव से जुड़ा हुआ है। चंदा, प्रचार और प्रभाव बढ़ाने का हर तरीका पूंजीवादी रास्ते से होकर जाता है और युवाओं के पास इसके लिए समय नहीं है। जो राजनीति में जाना चाहते हैं, वे भी जानते हैं कि पहले खूब पैसा कमाना होगा। इसलिए अमेरिका युवा कॉलेज से निकलते ही किसी काम में लग जाते हैं। राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी युवा कानून, सेना या फिर स्थानीय राजनीति का रास्ता अपनाते हैं। अमेरिका के 32 राष्ट्रपति पूर्व में सेना में रहे, 27 राष्ट्रपति वकील रहे, जबकि 20 गवर्नर रहे। इनमें से कई पहले सीनेटर भी रहे या विदेश सेवा या अन्य सार्वजनिक पदों पर काम कर चुके थे। वहां भारत की तरह फुलटाइम राजनीति कम लोग कर पाते हैं क्योंकि किसी भी पद पर आने के लिए दिखाना पड़ता है कि आपने पहले क्या किया है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कॉरपोरेट, जो प्रचार अभियान के लिए धन देते हैं। कंपनियां चाहती हैं कि बिजनेस के मामले में नीतियों में बहुत बदलाव न हो और अगर हो भी, तो उनके पक्ष में हो। इसे यथास्थिति बनाये रखना कहा जाता है। जब ट्रंप जीत कर आये, तो अपने रैडिकल फैसलों के कारण उन्होंने पारंपरिक कॉरपोरेट जगत को नाराज किया। मसलन, नाटो को खत्म करने की उनकी पहल, जो सफल नहीं हुई, संयुक्त राष्ट्र से प्रतिनिधि बुलाना, उत्तर कोरिया से दोस्ती, जलवायु समझौते से हटना आदि कई ऐसे कदम थे, जो पारंपरिक अमेरिकी राजनीति के अनुकूल नहीं थे। नतीजा, वे हार गये। अगर हम बाइडेन के कार्यकाल को देखें, तो एक तरह से पुरानी राजनीति बहाल हुई। उनके आते ही यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया और अमेरिकी हथियार लॉबी अपने हथियार बेच पाने में सफल होने लगी। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी लोग यह सब नहीं समझते हैं।

लोगों को पता है कि कॉर्पोरेट या बिग बिजनेस ही असली खिलाड़ी हैं। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने, तो कई लोगों को यह उम्मीद थी कि एक नयी सुबह होगी, एक नया अमेरिका बनेगा, जिसमें बेहतरी के लिए जगह होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्वांतानामो बे को बंद करने के अपने सबसे बड़े वादे से वे मुकर गये। उन्होंने सीरिया पर हमले किये और हर वह काम किया, जो पारंपरिक बिजनेस उनसे उम्मीद करता था। हेल्थकेयर की दिशा में ओबमाकेयर के नाम से जो नीति आयी, वह लगभग असफल रही क्योंकि अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा उद्योग को यह पसंद नहीं था। यह हो सकता है कि ओबामा के बाद अमेरिकी लोगों में एक निराशा घर कर गयी कि बदलाव संभव नहीं है, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस निराशा को भुनाया और 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' का नारा दिया। फिर आगे जो हुआ, वह हमारे सामने है। आम लोग यही कहते हैं कि हमें दो खराब नेताओं में से एक को चुनना है।

आज का इतिहास

1943 अमेरिकी ने न्यू जॉर्जिया से एनोगाई की लड़ाई पर जीत हासिल की।

1957 इस्लामी धार्मिक नेता और मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य आगा खां का निधन हुआ।

1957 राजकुमार करीम अल-हुसैनी ने सुल्तान महोम्द शाह अस्तेय खान को शिया इस्माइली मुसलमानों का 49 वां इमाम बनने में कामयाबी हासिल की।

1960 कांगो संकट के दौरान कांगो का राज्य कांगो से अलग हो गया। यह एक ऐसा दौर था जिसमें कई तरह के गृहयुद्ध शामिल थे। यह बेल्जियम से कांगो की स्वतंत्रता के ठीक बाद हुआ। विपरीत पक्ष जो युद्ध में लड़ रहे थे, उन्हें शीत युद्ध की अवधि में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का समर्थन प्राप्त था।

1960 किल टू मॉकिंगबर्ड, हार्पर ली का एक उपन्यास, जिसमें थीमोफ़ नस्लीय अन्याय की विशेषता थी और पहली बार अमेरिकनडिप साउथ में मासूमियत का विनाश हुआ था।

1962 उपग्रह टेलीविजन का पहला ट्रान्साटलांटिक प्रसारण किया गया था। यह संचार उपग्रह के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम के संकेतों को प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली है। इस प्रणाली के आविष्कार से पहले, विनिमय के लिए केबल नेटवर्क का उपयोग किया जाता था।

1962 नासा ने मानवयुक्त मिशन चंद्रमा के लिए घोषणा की। चंद्र की परिक्रमा करने वाले मिशनों की घोषणा भी की गई थी। नासा ने इस परियोजना को प्रोजेक्ट अपोलो नाम दिया। यह मिशनों की एक श्रृंखला थी जिसमें कई चंद्र प्रक्षेपण हुए और अंत में चंद्रमा पर मानव लैंडिंग के साथ समाप्त हुआ।

1975 चीन में 2200 वर्ष पुरानी कब्रगाह खोजी गयी जिसमे सैनिकों के 3000 आदमकद मूर्तियाँ दफ़न थी।

1977 मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया।

1977 मार्टिन लूथर किंग जूनियर को राष्ट्रपति पदक से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। वह एक महान मानवतावादी और कार्यकर्ता थे। नस्लवाद के खिलाफ अमेरिका में गैर-हिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलनों के लिए वह सबसे अच्छा था। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ़ फ्रीडम यूएसए का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

1981 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने अपना 13 सप्ताह की हड़ताल समाप्त कर की।

1986 न्यूजीलैंड की संसद ने समलैंगिक कानून सुधार को पारित कर दिया, जो कि समलैंगिक यौन संबंध को वैध बनाता है।

रूस किसका पक्का दोस्त है, भारत या फिर चीन?

अभिनय आकाश

8 जुलाई 2024 को रूस की राजधानी मॉस्को में दोपहर के वक्त आसमान में पंछी जैसी सफेद चीज नजर आई। जैसे-जैसे वो चीज करीब पहुंची उसका आकार बढ़ता गया। कुछ मिनटों के बाद एक विशालकाय विमान वेणुकोवो-II इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर खड़ी हो गई। इस विमान पर सुनहरे अक्षरों में भारत लिखा था। इस राजकीय विमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गॉर्ड ऑफ ऑर्नर और सलामियों के दौर के बीच रूस की धरती पर अपना कदम रखा। पूरे पांच बरस बाद मोदी रूस की यात्रा पर हैं। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी का तीसरा और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पांचवा कार्यकाल शुरू हुआ है। इस बीच रूस यूक्रेन के बीच की जंग तीसरे साल में पहुंच चुकी है। रूस की चीन के साथ नजदीकी बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ी हैं। बैलेस्टिक मिसाइलें हो या हथियारों के कलपुर्जे चीन पश्चिमी प्रतिबंधों की परवाह किये बिना इसकी सप्लाई कर रहा है। चीन रूस का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी बन गया है। ऐसी स्थिति में ये सवाल बड़ा है कि रूस किसका पक्का दोस्त है, भारत या फिर चीन?

चीन और भारत दो ऐसे देश जिनका अभी भी सरहद पर गतिरोध टूटा नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी भी दोनों देशों की सेनाएं खड़ी हैं। ऐसे में भारत के लिए भी क्या इस समय इस बात पर भरोसा कर पाना कि रूस भारत से अपनी दोस्ती अलग रखता है और चीन के साथ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत का भरोसा टूटे। वैसे इतिहास में रूस ने ऐसा कभी किया नहीं है। लेकिन वर्तमान दौर में रूस के पास गिने चुने दोस्त हैं। ऐसे में पीएम मोदी का मॉस्को दौरा काफी अहम नजर आता है। भारत पश्चिमी देशों के ज्यादा करीब नजर आता है तो चीन की तरफ से सीमा पर हरकतें ज्यादा बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन रूस और भारत के रिश्ते अच्छे हैं। भारत रूस की इकोनॉमी में भी मददगार है। रूस भी चीन की आक्रमकता को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। हालांकि कई जानकार बताते हैं कि भारत के लिए रूस कभी चीन के खिलाफ नहीं जाएगा।

18 मई 2024 में जब व्लादीमिर पुतिन बीजिंग के दौरे पर पहुंचे। पुतिन ने अपने पांचवें कार्यकाल के पहले विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना। वही जिनपिंग ने उन्हें गले लगा करके दिखाया कि रूस के साथ चीन के रिश्ते सबसे सुनहरे दौड़ में पहुंच गए हैं। सवाल ये है कि पुतिन और जिनपिंग की बढ़ती करीबी भारत के लिए क्या मायने रखती है। 22 मार्च 2023 यानी कि ठीक 1 साल पहले

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मास्को के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान वतन वापसी से पहले जिनपिंग बहुत बड़ी बात कहते हैं। जिनपिंग उस समय रूस की यात्रा की कुछ वक्त पहले ही अंतरराष्टीय अपराध न्यायलय ने युद्ध अपराधों के लिए पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। दोनों नेताओं ने इसे बिना किसी सीमा वाली साझेदारी को बढ़ाने वाली यात्रा बताया।

रूस जिससे करीबी बढ़ा रहा है, इसकी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले पांच साल से भारत के खिलाफ सैन्य सामान लेकर बैठी है। भारत और रूस के बीच केवल तेल और रक्षा हथियारों का व्यापार होता है लेकिन चीन के साथ व्यापार का स्तर काफी व्यापक है। वैसे भारत रूस रिश्तों में चीन के फैक्टर को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर धर्मसंकट में फंस गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के वक्त प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को उम्मीद थी कि उसका आजमाया हुआ दोस्त सोवियत संघ साथ देगा। लेकिन तत्कालीन सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव उसी दौरान क्यूबा मिसाइल संकट में फंसे थे। कहा जाता है कि खुश्चेव ने उस वक्त नेहरू से दो टूक कहा था कि वो सीमा समझौता कर लें क्योंकि उन्हें चीन के समर्थन की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस ने कहा था कि भारत अगर इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर जाता है तो रूस चीन के साथ खड़ा रहेगा। रूस ने भारत-चीन युद्ध में अपनी तटस्थता दिखाने के लिए भारत को सैन्य विमानों की बिक्री भी निलंबित कर दी। हालांकि, जल्द ही भारत-रूस के संबंध सामान्य हो गए थे।

भारत के प्रधानमंत्री मॉस्को में हैं। पुतिन और मोदी के बीच विभिन्य मुद्दों पर बात होगी। भारत और रूस बहुत ही नजदीकी साझेदार रहे हैं। सामरिक तौर पर रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। लेकिन आज विश्व की परिस्थितियां बदली हैं। कारोबार का तराजू इस वक्त रूस के पक्ष में है जिसे संतुलित करने के लिए भारत का जोर रहेगा। 2023-2024 के बीच भारत और रूस के बीच 54 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। भारत ने 45.4 लाख करोड़ रुपये का कच्चा तेल खरीदा। वहीं करीब 3.3 लाख करोड़ का भारत ने निर्यात किया। इस तरह से व्यापार घाटा रूस संग रिश्तों में बड़ा मुद्दा बन चुका है। कोविड के दौरान और उसके बाद भी भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा पहुंचा। अब रूस से कोयला लेकर दो ट्रेनें भारत आ रही है। ये जिस रूट का इस्तेमाल करेगी उसका नाम इंटरनेशनल नार्थ साउथ ट्रासपोर्ट कॉरिडोर यानी आईएनएसटीसी है।

आईएनएसटीसी करीब 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। इसमें रेल, रोड और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ये भारत को सेंट्रल एशिया होते हुए सीधे रूस से कनेक्ट करता है। रूस से चली ट्रेनें ईरान के चाबहार बंदरगाह से समुद्री रास्ते से होते हुए मुंबई पहुंचेगी। यानी जहां रेलवे ट्रैक होगा वहां ट्रेन चलेगी। जहां समुद्री रास्ता होगा वहां समुद्री जहाजों के जरिए माल पहुंचाया जाएगा। आईएनएसटीसी ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है। ये भारत के व्यापार के लिए बहुत मायने रखता है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस को समुद्री व्यापार पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस गलियारे का आर्थिक और रणनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। भारत इसे चीन के महत्वकांक्षी बेल्ट रोड इनिसिएटिव के विकल्प के रूप में देखता है।

दलितों-मुसलमानों के दम पर वापसी करने की तैयारी में कांग्रेस

अमित शर्मा

लोकसभा चुनाव में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच साथ मिलकर चुनाव लड़ने का समझौता हुआ था, तभी भाजपा ने इसे मजबूरी का समझौता बताया था। भाजपा का आरोप था कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ रहे हैं, जबकि उनके बीच में किसी भी तरह का कोई सामंजस्य नहीं है। पार्टी ने यह भी संभावना जताई थी कि चुनाव के बाद यह गठबंधन टूट जाएगा और दोनों दल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाएंगे। भाजपा का आरोप अब बिल्कुल सही साबित हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है और दोनों दलों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग-अलग उतरने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के तीनों लोकसभा प्रत्याशियों उदित राज, जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने स्वीकार किया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान उनका साथ नहीं दिया, जिसके कारण उनकी करारी हार हुई। इसके पीछे के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब उसका प्रदर्शन इससे कहीं बेहतर रहा था। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने अपने नेता पीएल पुनिया, रजनी पाटिल और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव की नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने तीनों लोकसभा प्रत्याशियों से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में तीनों प्रत्याशियों ने यही दावा किया है कि आम आदमी पार्टी नेता और कार्यकर्ता ने चुनाव में उनका साथ नहीं दिया। उन्हें इस बात का डर था कि यदि कांग्रेस दिल्ली में खड़ी हो जाएगी, तो इससे विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसक सकती है। यही कारण है कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में कोई सामंजस्य नहीं बना और कांग्रेस को अपने हिस्से की सभी तीनों सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने मीडिया से कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी के ही कई नेता असहज थे। उनका मानना था कि कांग्रेस को अकेले दम पर चुनाव में उतरना चाहिए और उसे केजरीवाल के भ्रष्टाचार का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहिए। लेकिन %बड़े उद्देश्यों% को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ रही पार्टी ने अंतत: कई अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय किया। हालांकि इसका उसे कोई लाभ नहीं मिला। दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ने के बाद भी एक भी सीट पर सफलता नहीं हासिल कर सके। कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने कहा कि पूरे देश में मुसलमान और दलित मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है। उनके अंदर यह भावना प्रबल हो गई है कि यदि देश में धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिज्म) और भाईचारे को यदि कोई बचा सकता है तो वह कांग्रेस ही है। दलित समुदाय इस बात से बहुत आशंकित रहा कि भाजपा को पूर्ण बहुमत की सत्ता मिल जाने के बाद देश के संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए उसने पूरे दमखम के साथ कांग्रेस का साथ दिया और पूरे देश में भाजपा को हराने का काम किया। अब कांग्रेस अपने इन्हीं दो मूल मतदाता वर्ग को अपने साथ लेते हुए अन्य समाज के लोगों को भी साधने का काम करेगी। कांग्रेस नेता ने विश्वास जताया कि पार्टी दिल्ली में एक बार फिर मजबूत वापसी करने में सफल रहेगी। कांग्रेस की पूरी उम्मीद मुसलमान और दलित मतदाताओं के समर्थन पर टिकी हुई है। मुसलमान मतदाता पूरे देश में रणनीतिक वोटिंग करने के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि मुसलमान मतदाता उसी राजनीतिक दल को वोट करता है, जो भाजपा को हराने की स्थिति में होता है। ऐसे में पिछले तीन लोकसभा चुनाव और तीन विधानसभा चुनाव में शून्य पर अटक रही कांग्रेस को मुसलमान मतदाता क्यों वोट देंगे, यह बात समझ पाना कठिन है।

उत्तर प्रदेश भाजपा में क्यों नहीं उभर रही है दलित लीडरशिप

अजय कुमार

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से जो झटका मिला है, उससे बीजेपी आलाकमान अभी तक उबर नहीं पाया है। हार की कई स्तरों पर लगातार समीक्षा हो रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की हार और वोट प्रतिशत में गिरावट के लिये फिलहाल कई छोटे-छोटे के अलावा दो-तीन बढ़े कारण नजर आ रहे हैं। इसमें प्रत्याशियों के प्रति जनता की नाराजगी के अलावा ओबीसी और दलित वोट बैंक के खिसकने को सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है। इसी के चलते पार्टी के सजातीय मंत्रियों और पदाधिकारियों की लगाम कसने के साथ अब इस वोट बैंक को वापस भाजपा की तरफ लाने की जिम्मेदारी भी सजातीय नेताओं को सौंपी गई है। भाजपा आलाकमान दलित मंत्रियों के साथ ही अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिसकी ओर अभी तक ना तो बीजेपी आलकमान और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्यान दिया है। इसमें सबसे बड़ा कारण पार्टी और सरकार के स्तर पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरी सरकार को अपने पास केन्द्रित कर लेना है। स्थिति यह हो गई थी कि यूपी में योगी ही सब कुछ हो गये थे, यहां तक की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक यूपी प्लस योगी बहुत हैं उपयोगी जैसे जुमले बोलने लगे थे।

स्थिति यह हो गई थी कि जो वोटर अपने जनप्रतिनिधि से सीधे सम्पर्क में रहता है उसी जनप्रतिनिधि के अधिकारों को सीज कर दिया गया था,कई मौकों पर वह (विधायक/सांसद) अपने वोटरों को चाह कर भी इंसाफ नहीं दिला पाते थे, क्योंकि उनकी न तो सरकार में सुनवाई हो रही थी, न ही अधिकारी अथवा पुलिस उनकी सुनती थी। क्योंकि ऊपर से आदेश पास हुआ था कि कोई बीजेपी का नेता किसी सरकारी अधिकारी अथवा थाना-चौकी पर नहीं जायेगा। ऐसे में कोई नेता या जनप्रतिनिधि थाने-चौकी पर जाने की हिमाकत कर लेता था तो उसको बेइज्जत होना पड़ता था। नतीजा यह होता जनप्रतिनिधि अपने ही मतदाताओं की नजरों में उतर जाता। वह वोटरों से कटने लगता, जिसकी परिणिति लोकसभा चुनाव में हार के रूप में बीजेपी को चुकानी पड़ी।

अब जब बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है तो वह अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उनके द्वारा दलितों और ओबीसी समाज में भाजपा को लेकर नाराजगी की वजहें गिनाई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो कई मंत्रीं और नेता बेरोजगारी के अलावा पार्टी में जातीय कार्यकर्ताओं को तवज्जों न मिलना हार का एक बड़ा कारण बता रहे हैं।कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष किसी दलित को बनाया जाये, जिससे दलित वोटरों में अच्छा मैसेज जायेगा। कुछ लोगों ने तो यह भी आरोप लगाये कि दलित अधिकारियों को थानेदारों और तहसीलदारों की नौकरियां तो मिलती हैं लेकिन उन्हें पोस्टिंग में दरकिनार रखा जाता है। पार्टी नेताओं ने आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्ट की नौकरी में दलित-ओबीसी समाज के लिए आरक्षण नहीं होने को राज्य में पार्टी की हार की बड़ी वजह बताया है। सरकार और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज नेताओं ने कहा कि यह चिंतनीय है कि आखिर सरकार के बेहतर काम के बावजूद लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक तरीके से पहली बार बसपा से कट कर दलित वोट सपा और कांग्रेस की ओर चला गया, ऐसा आखिर क्यों हुआ ? इसका कारण बताते हुए नाराज नेताओं ने दलित नेतृत्व को आगे न बढ़ाने की बात रखी।

खैर, बीजेपी आलाकमान ने एहतियात के तौर पर जो कदम उठाये हैं उसमें लोकसभा चुनाव के परिणाम से सीख लेते हुए भाजपा ने दलितों में नए सिरे से पैठ बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार व संगठन में दलितों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। यूपी भाजपा का नया अध्यक्ष भी कोई दलित चेहरा हो सकता है। इस पर भी विचार हो रहा है कि उप्र की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव में सिफारिश की बजाय जीतने वाले उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए। उप चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही तय किया गया कि टिकट वितरण से पहले स्थानीय नेताओं की राय जरूर ली जाएगी। इसके साथ ही हिदायत दी गई है कि सभी भाजपा नेताओं को अहंकार से दूरी बना कर चलना होगा। सभी को पद नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन समर्पित होकर चलने से समय आने पर पार्टी आगे आने का मौका भी देती है।

बहरहाल, हार के कारणों का पता लगाने की कोशिशों के साथ पार्टी आलाकमान ने दलित व ओबीसी नेताओं को फिलहाल दस विधानसभा के लिए होने वाले उप चुनाव पर फोकस करने को कहा है। सभी लोग मिलकर सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतने की कोशिश में जुटें। नेताओं को आपसी मतभेद भूलकर हर सीट जीतने की रणनीति बनाकर काम करना होगा।

इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश भाजपा की मीडिया टीम की भूमिका की भी समीक्षा कर रहे हैं। संतोष ने मीडिया के पदाधिकारियों को अपने तेवर और कलेवर को और अधिक दुरूस्त करने के साथ ही सोशल मीडिया पर सरकार और संगठन का पक्ष आक्रमकता से रखने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार की वजहों को भी जाना और उन कमियों के बारे में भी पूछा, जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। संतोष ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर दलितों और ओबीसी के बीच फैलाए गए बातों का असर कम करने के लिए अभी से जुटने के भी निर्देश दिए।

कंजर्वेटिव को मात की पटकथा पहले ही तैयार थी

दीपक वोहरा

ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में 14 साल बाद लेबर पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है और कंजर्वेटिव पार्टी की बुरी तरह हार हुई है। ऋषि सुनक ने अपनी हार मान ली है और उन्होंने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर को जीत की बधाई भी दी है। अब कीर स्टार्मर का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया है।

दरअसल, सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की हार की पटकथा लगभग उसी समय लिखी जा चुकी थी, जब बीते मई में निवर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अचानक चुनाव की घोषणा करके पूरे देश को चौंका दिया था। वास्तव में कंजर्वेटिव पार्टी को यकीन नहीं था कि वे शरणार्थियों (खासकर मुसलमानों) की रिकॉर्ड संख्या को आने से रोक पाएंगे। इस चुनाव में कंजर्वेटिव ने कई वादे किए, जिनमें कुछ शरणार्थियों को रवांडा भेजने की बेहद विवादास्पद योजना भी शामिल थी।

दूसरी तरफ, ब्रिटिश जनता कई समस्याओं से जूझ रही थी। जैसे बढ़ती महंगाई ने उनके घर का बजट बिगाड़ दिया। इसके अलावा, उन्हें लगता है कि अनियंत्रित इस्लामी शरणार्थियों की समस्या ब्रिटिश जीवन-शैली को बर्बाद कर रही है, कभी दुनिया भर में प्रशंसित शिक्षा प्रणाली बर्बाद हो रही है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त हो गई है, लोगों को रहने के लिए सस्ता घर नहीं मिल रहा है और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। यहां तक कि प्रवासी भारतीय भी कंजर्वेटिव पार्टी से दूर जा रहे थे, क्योंकि ये समस्याएं उन्हें भी परेशान कर रही हैं।

चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले इन मुद्दों से निपटने के बजाय निवर्तमान प्रधानमंत्री यूक्रेन युद्ध में रूस को हराने के लिए अमेरिकी रथ में सवार हो गए। करदाताओं का पैसा बेकार के प्रयासों में बर्बाद किया जा रहा है, जबकि यूक्रेन नष्ट हो चुका है। असल में ब्रिटेन आज यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के अपने आत्मघाती कदम से जूझ रहा है, जिसने वहां की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। वह हताश होकर अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि बेहतर करना चाहता है, जबकि उसने वैश्विक मामलों में नाटकीय ढंग से अपनी कम हुई भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। इन्हीं वजहों से संसदीय चुनावों

में लेबर पार्टी ने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को आराम से हरा दिया।

लेबर पार्टी के उदय के लिए किसी लोकप्रिय नीति की तुलना में रूढ़िवादी विस्फोट को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कई प्रयासों के बाद एक दशक पहले भी ग्रेट ब्रिटेन बड़ी मुश्किल से स्कॉटिश स्वतंत्रता के जनमत संग्रह से बच पाया था। इस तरह का प्रयास फिर से होगा, क्योंकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। स्कॉटिश लोग फिर से यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन की प्रतिष्ठा बहुत नीचे गिर चुकी है। लंदन में अब वह बात नहीं रही। मई, 2024 में एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ने माना कि दुनिया का 40 प्रतिशत अवैध धन लंदन में आता है। भ्रष्ट राजनेताओं, नौकरशाहों, व्यापारियों आदि द्वारा पैदा किए गए काले धन के लिए इंग्लैंड दुनिया की सबसे बड़ी पनाह बन गया है। भारत के कई घोषित आर्थिक अपराधी लंदन में छिपे हुए हैं, जिनमें से कुछ लोग भारतीय बैंकों के साथ की गई धोखाधड़ी के खिलाफ मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने की अपेक्षा ब्रिटिश जेल में रहना पसंद करते हैं। जबकि ब्रिटेन ने जुलाई, 1989 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के गठन में बहुत सक्रियता दिखाई, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्डरिंग, आतंकवादियों को फंडिंग और सामूहिक विनाश के हथियारों की फंडिंग से निपटने के उपायों को विकसित करना था।

इंग्लैंड अतीतवाद से ग्रस्त है। वह कभी महान रह चुके अपने अतीत के साथ जीना पसंद करता है। जनवरी 2020 में, ब्रिटेन ने दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए फास्ट-ट्रैक वीजा देने की घोषणा की, जिसमें ब्रिटेन आने वाले योग्य लोगों की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। एक समय दुनिया का लगभग एक चौथाई हिस्सा ब्रिटेन के अधीन था। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। हम भारत के लोगों ने ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का विध्वंस किया, क्योंकि हमने गैर-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य ध्वस्त हो गया। 18वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी क्रांतिकारी बर्ट्रेंड बारेरे ने एंगलटेरे (अंग्रेजों की भूमि) को दुकानदारों का देश बताया था, जो ईमानदार होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में धोखेबाज होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विश्वासघाती अंग्रेज फ्रांस में एक आम कहावत बन गई थी। सुनक ने हाल में कुछ गलतियां कीं, जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जब वह कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब भी उनकी छवि को पार्टीगेट (कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री निवास में बोरिस जॉनसन के साथ जश्न मनाने) से झटका लगा था। संभवत: इससे भी ज्यादा नुकसान उन्हें वित्तीय मामलों को लेकर पारिवारिक विवाद के कारण हुआ। इसने उनकी लोकप्रियता को भारी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि कोविड सहायता योजना को लेकर उन्होंने अपनी अच्छी छवि बनाई थी, जिससे उन्हें परिवारों और व्यवसायों को बचाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई का श्रेय मिला था। हाल में उनकी आलोचना इसलिए हुई कि वह जीवन-यापन के संकट से जूझ रहे लोगों की मदद करने में सुस्त दिखे और लोगों से दूर होते दिखे। महंगी निजी वस्तुओं का दिखावा करने के चलते भी उनकी आलोचना हुई।

नवीनतम जनगणना के अनुसार, ब्रिटेन में गैर-ईसाई आबादी बढ़ रही है। अवैध प्रवासन के कारण मुसलमानों की संख्या वहां बढ़ रही है। इससे ब्रिटिश नाराज हैं। समय बदल जाता है, लेकिन मानसिकताएं स्थिर रहती हैं। यदि ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं होता, तो उसका वैश्विक प्रभाव सोमालिया के बराबर ही होता। हकीकत सामने है, लेकिन साम्राज्यवादी रवैया उसे स्वीकार करने से रोकता है। ऐसे में भला नस्लवादी अंग्रेज भारतीय मूल के ऋषि सुनक को कैसे बर्दाश्त करते? पता नहीं, सुनक ने इससे कुछ सबक सीखा या नहीं!

संसदीय बहस के लाइव प्रसारण पर विचार का वक्त

उमेश चतुर्वेदी

क्या वक्त आ गया है कि संसदीय कार्यवाही के लाइव टीवी प्रसारण पर विचार किया जाए? एक वर्ग का मानना है कि अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो संसद की गरिमा घटेगी। पूर्व उप-प्रधानमंत्री देवीलाल कहा करते थे कि लोकतंत्र लोक-लाज से चलता है। उसी अंदाज में कह सकते हैं कि महान परंपराओं और गरिमा को स्वीकार किये बिना कोई भी शासन सफल नहीं हो सकता। ब्रिटिश संसद में एक परंपरा है कि संसदीय कार्यवाही से हटाये गये शब्दों को न तो उद्धृत किया जा सकता है और न ही उसे रिपोर्ट किया जा सकता है। जाहिर है कि हटाये गये शब्द वे होते हैं, जो अमर्यादित, तथ्यहीन और गरिमा के विरूद्ध होते हैं। जब तक टेलीविजन नहीं था, पत्रकारिता के रंगरूटों को संसदीय इम्बार्गो और कार्यवाही की रिपोर्टिंग के मायने गहराई से समझाये जाते थे। संसद या किसी संसदीय समिति के बयान की जानकारी होने के बावजूद उसे तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था, जब तक की समय सीमा संसद या संसदीय समिति की ओर से तय की गयी होती थी। रिपोर्टर संसद की रिपोर्टिंग करते हुए सांसदों की उन बातों को भी सुनते ही थे, जिन्हें अमर्यादित और तथ्यहीन होने के चलते कार्यवाही से हटा दिया जाता था, पर वे उनका उल्लेख रिपोर्टों में नहीं करते थे। लाइव प्रसारण के चलते अब जनता तक वे सारी बातें भी पहुंच रही हैं, जिन्हें बाद में संसदीय कार्यवाही से निकाल दिया जा रहा है। दिलचस्प यह है कि सांसदों की बातों को जब रोका जाता है, तो वे इसे अपने प्रति दुर्भावना बताने लगते हैं। मौजूदा दौर विजुअल माध्यमों का है। ऐसे में हर सांसद चाहता है कि वह संसद में जो भी बोले, उसका प्रसारण हो। संसद की कार्यवाही का पहला प्रसारण 20 दिसंबर 1989 को दूरदर्शन पर शुरू हुआ। तब चुनिंदा कार्यवाही को दिखाया गया। फिर 18 अप्रैल 1994 से लोकसभा की पूरी कार्यवाही को फिल्माया जाने लगा। उसी साल अगस्त में सीधे प्रसारण के लिए संसद भवन में एक लो-पावर ट्रांसमीटर स्थापित किया गया। दिसंबर 1994 से दोनों सदनों के प्रश्नकाल का दूरदर्शन पर वैकल्पिक सप्ताह में सीधा प्रसारण होने लगा। तीन नवंबर 2003 को जब डीडी न्यूज शुरू हुआ, तो शीतकालीन सत्र से दोनों सदनों के प्रश्नकाल का प्रसारण डीडी चैनलों पर एक साथ होने लगा। लाइव प्रसारण के इतिहास में दो घटनाएं बहुत याद की जाती हैं। अक्तूबर 1990 में भाजपा की समर्थन वापसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव रखा। दो दिनों तक चली बहस का दूरदर्शन ने लाइव प्रसारण किया था। सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वीपी सिंह का समर्थन मांगना बेहद चर्चित रहा। तेरह दिन की वाजपेयी सरकार के विश्वास मत पर मई 1996 के आखिरी हफ्ते में हुई चर्चा में वाजपेयी ने दो शानदार भाषण दिये थे। माना जाता है कि उन भाषणों के बाद वाजपेयी की लोकप्रियता में अपार इजाफा हुआ। दो साल बाद सत्ता में उनकी वापसी में ये दोनों भाषण भी मील के पत्थर माने गये। इसके बाद से ही संसदीय बहसों में शामिल होने वाले सांसद लाइव प्रसारण की इच्छा पालने लगे। साल 2004 में वाजपेयी सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पहली सरकार आयी। तब लोकसभा के अध्यक्ष माकपा के सोमनाथ चटर्जी बने। उन्होंने संसदीय कार्यवाही के प्रसारण के लिए अलग से दो चैनलों का विचार दिया। इसी विचार को मूर्त रूप मिला दिसंबर 2004 में, जब दोनों सदनों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए एक अलग समर्पित सैटेलाइट चैनल की स्थापना की गयी। साल 2006 में लोकसभा टीवी ने निचले सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया, लेकिन राज्यसभा टीवी की शुरुआत तब नहीं हो सकी। मोटे तौर पर राज्यसभा टीवी की शुरुआत उस दौर के नेता प्रतिपक्ष और सभापति के बीच मतभेदों के चलते नहीं हो पायी। जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने, तो उन्होंने राज्यसभा टीवी के लिए अलग से एक चैनल की शुरुआत की। वह साल 2011 था। यह बात और है कि यह चैनल स्वतंत्र रूप से सिर्फ एक दशक ही चल पाया। एक मार्च 2021 को लोकसभा और राज्यसभा के चैनलों को एक कर संसद टीवी बना दिया गया।

ज्योतिष में है भविष्य

पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों का मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका अध्ययन ज्योतिष में किया जाता है। ज्योतिष के द्वारा ज्ञात हो सकता है कि कौन से ग्रह उस पर अच्छा प्रभाव डालेंगे और कौन से ग्रह बुरा। हर ग्रह का अपना एक तत्व होता है उस तत्व के द्वारा उस ग्रह के बुरे प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। वर्तमान में ज्योतिष एक संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है।

ज्योतिष ग्रहों को जानने की एक प्राचीन विद्या है। यह हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा प्रदत्त एक ज्ञान है। ज्योतिष ग्रहों की गणितीय गणना है। ज्योतिष का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति को अपनी अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति का ज्ञान हो जाता है, जिससे वह उसके अनुसार कार्य करता है तो विपरीत परिस्थितियों में भी उसे संबल मिलता है। पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों का मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका अध्ययन ज्योतिष में किया जाता है। ज्योतिष के द्वारा ज्ञात हो सकता है कि कौन से ग्रह उस पर अच्छा प्रभाव डालेंगे और कौन से ग्रह बुरा। हर ग्रह का अपना एक तत्व होता है उस तत्व के द्वारा उस ग्रह के बुरे प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। वर्तमान में ज्योतिष एक संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है। इस विद्या में कंप्यूटर के प्रयोग से ज्योतिष का क्षेत्र सरल एवं व्यापक हुआ है। भारत में ज्योतिष से संबंधित लगभग 1800 वेबसाइट्स हैं। विदेशों में ज्योतिष से संबंधित लगभग 2 लाख से अधिक वेबसाइट्स हैं। युवा ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर इसमें भी कैरियर बना सकते हैं। शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. विनायक पांडे के अनुसार ज्योतिष वर्तमान में एक अच्छे कैरियर क्षेत्र के रूप में उभरा है। कई युवा इस प्राचीन भारतीय विद्या के बारे में जानने-समझने को उत्सुक हैं। अभी इस विद्या का पूर्ण और सही ज्ञान रखने वालों की भारत में अभी भी कम है।

उन्होंने बताया कि ज्योतिष के दो प्रकार होते हैं- 1. सिद्धांत ज्योतिष और 2. फलित ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत पंचांग आदि का निर्माण शामिल है। इसका अध्ययन कर युवा खुद स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। फलित ज्योतिष के अंतर्गत भविष्य देखना, पत्रिका बनाना, ग्रहजन्य पीड़ा, निदान आदि का अध्ययन किया जाता है।

डॉ. पांडे कहते हैं कि ज्योतिष में रुचि रखने वाले युवा ज्योतिष में डिप्लोमा कर सकते हैं। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप किसी भी विषय में स्नातक की पढ़ाई के साथ यह डिप्लोमा कर सकते हैं। यह डिप्लोमा कोर्स तीन वर्षीय है। पहले साल में उत्तीर्ण होने पर प्रमाण-पत्र दिया जाता है। दूसरे वर्ष में डिप्लोमा और तीसरे वर्ष में एडवांस डिप्लोमा होता है। यह युवाओं के लिए उभरता हुआ कैरियर क्षेत्र है। ज्योतिष के साथ में आध्यात्मिक जुड़ाव भी होना चाहिए।

आइए जानते हैं कुछ इंटरव्यू टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं। समय से पहले न पहुचें- समय से पहले पहुंचने पर इंटरव्यूअर पर आपके प्रति नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समय का पाबंद रहना अच्छा गुण है। इस बात का ध्यान रखें कि आप न देर से पहुंचे और न समय से पहले पहुंच कर वहां खाली बैठे रहें। कुछ हायरिंग मैनेजरों को कैंडिडेट्स का बिना वजह खाली बैठे रहना पसंद नहीं आता।

प्रचलित चिकित्सा पद्धति के नुकसान के चलते जहां लोगों में आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचलन बढ़ रहा है वहीं कुछ वर्षों से योग के प्रति भी लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है। यदि कोई व्यक्ति योग शिक्षक बनना चाहता है तो उसे योग की तमाम अपेक्षित जानकारी होनी चाहिए।

योग में संवारे कैरियर

इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। योग शिक्षा और प्रशिक्षण के बाद आप स्वयं योग-कक्षाएं लगा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास साफ-सुथरा स्थान तथा स्वस्थ माहौल होना चाहिए। खुली जगह सर्वोत्तम रहती है। यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण लिया है तो आप स्कूल, कॉलेज में भी कक्षाएं ले सकते हैं। चिकित्सक और शोधकर्ता के रूप में आप रोगों तथा विकारों के संबंध में कार्य कर सकते हैं। योग में अनेक क्षेत्र हैं, लेकिन दो प्रमुख क्षेत्र हैं -1. अध्यापन और अनुसंधान तथा 2. रोगों का उपचार। जहां तक रोगों के उपचार का संबंध है, योग मन और शरीर- दोनों का इलाज करता है। किंतु यह जानना जरूरी होता है कि किस आसन और प्राणायाम से कौन-सा रोग ठीक होता है। इसके लिए विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाती हैं, जहां उन्हें विभिन्न आसन और योग के अन्य पहलू सिखाए जाते हैं। योग पर अनेक ग्रंथ हैं। उक्त ग्रंथों का अध्ययन कर योगाभ्यास की सही तकनीक समझ सकते हैं। योग में प्रशिक्षण लेना बेहद जरूरी है क्योंकि यदि व्यायाम सही ढंग से नहीं किया जाता है तो समस्या बढ़ सकती है। यदि समुचित प्रशिक्षण के बिना योग किया जाता है तो यही योग हानिकारक भी हो सकता है।

रोजगार की संभावनाएं

वर्तमान में भारत में 30 से ज्यादा कॉलेजों में योग विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र के स्नातक योग से संबंधित पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर ये पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर का एक वर्ष का पाठ्यक्रम भी कराया जाता है। यहां यह भी जानना आवश्यक है कि कॉलेजों के अलावा देशभर में कई योग अध्ययन केंद्र भी हैं। योग पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल हैं- शरीर रचना, दर्शन, ध्यान, व्यायाम तथा योग और ध्यान का सिद्धांत व नियम। व्यावहारिक पक्ष में योगासन, सूर्य नमस्कार तथा प्राणायाम जैसे विभिन्न आसन दिखाए जाते हैं।

इंटरव्यू की खास बातें

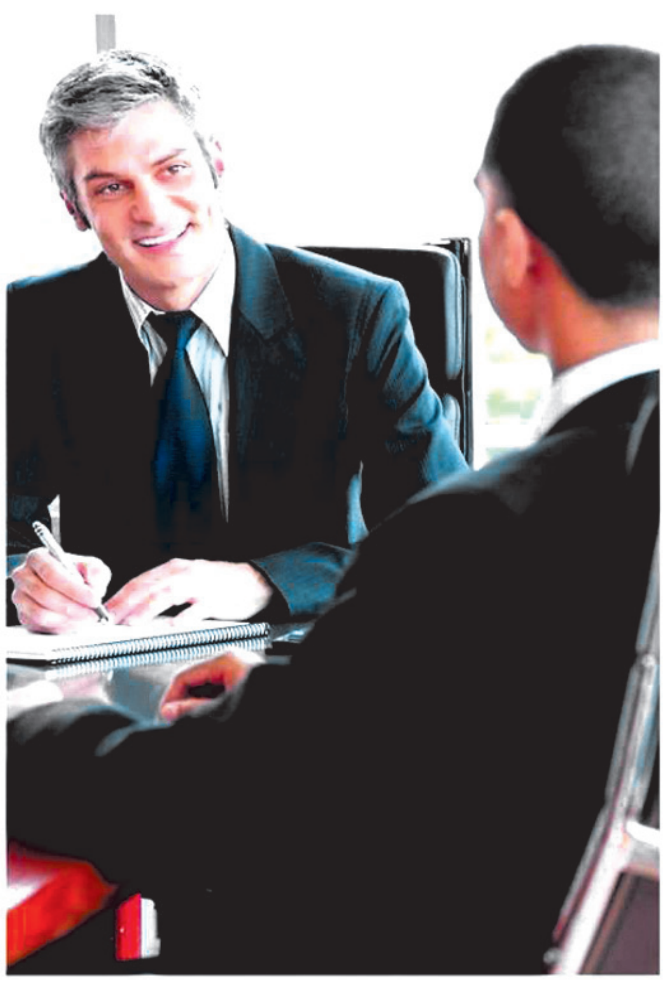

कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देते समय आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप इंटरव्यू में अपने आपको सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। आइए जानते हैं कुछ इंटरव्यू टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं। समय से पहले न पहुचें- समय से पहले पहुंचने पर इंटरव्यूअर पर आपके प्रति नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समय का पाबंद रहना अच्छा गुण है। इस बात का ध्यान रखें कि आप न देर से पहुंचे और न समय से पहले पहुंच कर वहां खाली बैठे रहें। कुछ हायरिंग मैनेजरों को कैंडिडेट्स का बिना वजह खाली बैठे रहना पसंद नहीं आता।

हरेक गतिविधि पर नजर- इंटरव्यू देते वक्त आपका ध्यान सिर्फ उसी पर रहता है। इंटरव्यूअर आपसे सवाल-जवाब करने के दौरान आपकी प्रत्येक हलचल पर ध्यान रखता है। कई कंपनियों में तो कैंडिडेट्स के व्यवहार को देखने के लिए रिसेप्शन पर कैमरे तक लगाए जाते हैं। हायरिंग मैनेजर इन कैमरों से यह देखते हैं कि आप रिसेप्शनिस्ट और दूसरे इंटरव्यू देने आए प्रतिभागियों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बातों को बढ़ा-चढ़ाकर न बोलें- इंटरव्यू के दौरान अनावश्यक न बोलें। आपसे जो सवाल किया जाए, उसी का सीधे तरीके से जवाब दें। कई लोगों की आदत जरूरत से ज्यादा बोलने की होती है। इंटरव्यूवर को इस बात से सख्त नफरत होती है कि आप उसके सवाल का जवाब देने की बजाय इधर- उधर की बातें करें। अगर आप फालतू की बात करेंगे तो यही माना जाएगा कि आपको कुछ पता नहीं है। सकारात्मक जवाब- इंटरव्यू के दौरान अपने पॉजीटिव एटीट्यूट को प्रदर्शित करें। इंटरव्यू के दौरान आपसे चाहे जितने नकारात्मक प्रश्न पूछे जाएं, आप उनका जवाब पॉजीटिव ही दें। इंटरव्यू के दौरान ज्यादा कम्फर्टेबल और फ्रेंडली होने का प्रयास भी न करें। अपने इंप्लोयर की न करें आलोचना- आप अपने वर्तमान जॉब से चाहे कितने ही असंतुष्ट क्यों न हों, लेकिन इंटरव्यू के दौरान अपने इंप्लोयर की किसी भी तरह की आलोचना न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इंटरव्यू पैनल में आपके बारे में गलत संदेश जाएगा।

फोटोग्राफी में ध्यान दें बारीकियों पर

फैशन और वाइल्ट लाइफ फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले युवा इसे अपना पेशन मानते हैं। इस फील्ड में क्रिएटीविटी, टेक्निक, ट्रेनिंग, हार्डवर्क, ग्लैमर, एडवेंचर सब कुछ है। सही ट्रेनिंग और गाइडेंस से इस फील्ड में कैरियर बनाने का स्कोप बढ़ गया है। कई डिग्री होल्डर फोटोग्राफर्स भी फैशन और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बारीकियां सीख रहे हैं। कैरियर संभावनाएं- फैशन इंडस्ट्रीज, कार्पोरेट और इंडस्ट्रीयल सेक्टर के विकसित होने से इस फील्ड में संभावनाएं बढ़ गई हैं। फैशन इंडस्ट्री के फलने-फूलने के साथ ही फैशन फोटोग्राफी में ग्लैमर जुड़ चुका है। आज हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ कैलेंडर, मैगजीन, विज्ञापन ब्रोशर प्रकाशित करती है। इनमें आकर्षक और स्टाइलिश फोटो की खास भूमिका

होती है। इन सबके लिए फैशन फोटोग्राफर की बहुत जरूरत है। तकनीकी रूप से सक्षम होने पर इस क्षेत्र में भविष्य बहुत उज्जवल है। शैक्षणिक योग्यता- फोटोग्राफी के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। देशभर में कई इंस्टीट्यूट फोटोग्राफी में डिग्री या सर्टीफिकेट कोर्स करवाते हैं। एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनने के लिए डीप स्टडी और अच्छे विजन का होना जरूरी है। अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, औरंगाबाद जैसे शहरों में संस्थानों द्वारा फोटोग्राफी का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता है। इन संस्थानों में दो-तीन वर्षों के डिग्री कोर्स एवं ट्रेनिंग दी जाती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंने लोकसभा स्पीकर जाएंगे रूस

नई दिल्ली। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में गुरुवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस मंच का मुख्य विषय 'समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका' है। बिरला के साथ प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी व राज्यसभा सदस्य शंभूशरण पटेल शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अजरबैजान, आर्मिनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान के अध्यक्ष, सांसद व अंतर-संसदीय संघ की अध्यक्ष तुलिया एक्सन भी हिस्सा लेंगे।

केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 तक स्थगित

नईदिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई बुधवार को 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में केजरीवाल के जवाब पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले को 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले, दिल्ली के सीएम को उनके खिलाफ ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने जमानत दे दी थी। लेकिन, दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

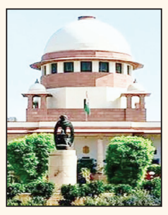

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संदेशखाली केस में बिना पूर्व अनुमति के सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने की चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को वैध करार दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिका को स्वीकारते हुए केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया। इस याचिका में ये बताया गया है कि राज्य सरकार की सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद केंद्रीय एजेंसी मामले की जांच कर रही है। शीर्ष अदालत ने राज्य में सीबीआई जांच पर पश्चिम बंगाल सरकार के मुकदमे की अगली सुनवाई 13 अगस्त को करेगा, तब तक कोर्ट को स्थगित कर दिया गया। बंगाल सरकार ने 2018 में केंद्रीय एजेंसी को जांच के लिए राज्य द्वारा अपनी सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद मामले दर्ज करने पर सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सीएम योगी ने 7720 लेखपालों को बांटे नियुक्ति पत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। योगी ने यूपी भर्ती घोटाले को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पहले भर्तियों में घोटाले होते थे। यूपी सीएम ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, चाचा-भतीजा वसूली पर निकलते थे। अब ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब नौकरी के लिए किसी को किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में हमने 6 लाख सरकारी नौकरी बिना किसी भेदभाव के दी हैं। ये नौकरियां आरक्षण के नियमों के तहत दी गई हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति-पत्र वितरण को लेकर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि साल 2017 के पहले क्या होता था? लेखपालों के पद खाली क्यों थे?

तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तेजी से ध्यान आकर्षित किया है। फुटेज में नीतीश कुमार को एक इंजीनियर से पूछते हुए देखा जा सकता है, मुझे बताओ, क्या मुझे आपके पैर छूने चाहिए? जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, इंजीनियर पीछे हट जाता है और विनम्रता से मना कर देता है। नीतीश कुमार बिहार की राजधानी पटना में जेपी गंगा पथ पर गाय घाट से कंगना घाट तक 3.4 किलोमीटर लंबे पुल के उद्घाटन में शामिल हो रहे थे। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के हाथ जोड़ने और पैर छूने पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहाँ तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात-बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो?

ऑस्ट्रिया से दुनिया को पीएम मोदी का संदेश- समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता

वियना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों की युवा शक्ति और विचारों को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और कुशल कार्यबल की आवाजाही में सहयोग देगा। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति. सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है, समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। चाहे वह कहीं भी हो, मासूम लोगों के जान की हानि अस्वीकार्य है। भारत और ऑस्ट्रिया संवाद और कूटनीति पर जोर देते हैं और इसके लिए हम साथ मिलकर हर संभव मदद देने के लिए तैयार हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ख़ुशी है कि अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे ऑस्ट्रिया जाने का अवसर मिला। मेरी ये यात्रा ऐतिहासिक और खास है.% 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है...आज ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर और मेरे बीच बहुत सार्थक चर्चा हुई। हमने अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं पर चर्चा की। हमने इन संबंधों को एक रणनीतिक दिशा देने का फैसला किया है...बुनियादी ढांचे के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में...हम एक-दूसरे की क्षमताओं को जोड़ने की दिशा में काम करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने ऑस्ट्रिया के वियना के संघीय चांसलरी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के वियना में संघीय चांसलरी की अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर भी मौजूद थे। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने कहा कि वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था खुद को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में पाती है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है - एक दृढ़ता से निर्यात उन्मुख देश आर्थिक सहयोग के नए रूपों को खोजने के लिए। आज, पहले से ही हैं भारत के साथ उत्कृष्ट आर्थिक और व्यापारिक संबंध, आपसी विश्वास और आत्मविश्वास से चिह्नित हैं। वर्तमान व्यापार मात्रा 2.7 बिलियन यूरो है, 150 से अधिक ऑस्ट्रियाई व्यवसाय भारत में काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि संख्या में वृद्धि होगी।

गर्व के मौके पर नकारात्मकता फैलाने पर तुला हुआ है विपक्ष : भाजपा

नईदिल्ली। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि विपक्ष खुशी और गर्व के मौके पर भी नकारात्मकता फैलाने पर तुला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई भी शुभ अवसर हो, वे नकारात्मक और शर्मनाक टिप्पणियाँ करना शुरू कर देंगे। अब, वे हमसे यूक्रेन के बारे में पूछ रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपनी सीडब्ल्यूसी में रूस-यूक्रेन मुद्दे पर कोई प्रस्ताव पारित किया है! दरअसल, विपक्ष खासकर के कांग्रेस मोदी के रूस दौरे को लेकर खूब सवाल उठा रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने विपक्ष को ये जवाब दिया है।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व और संतुष्टि की अनुभूति का अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके कार्यों और शानदार नेतृत्व की अत्यधिक सराहना की

जाती है और उन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे पसंदीदा नेता बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये विषय सिर्फ एक सम्मान का नहीं है। मोदी जी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें फ्रांस, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरब और फिलिस्तीन जैसे देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। और आज रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द आर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को दिया है।

त्रिवेदी ने कहा कि अमेरिका कहता है कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है और रूस कहता है, भारत हमारा पारंपरिक सहयोगी है। पूरी दुनिया में किसी अन्य देश का इतना कद नहीं है कि इन देशों से ऐसी टिप्पणियाँ और बयान प्राप्त हो सकें। उन्होंने दावा किया कि इस समय मोदी जी एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिन्हें 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अवसर मिला और उसके साथ ही रूस ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक दिया है। विश्व का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इस परिस्थिति में नहीं है।

कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की पृष्ठभूमि में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री को कुछ घंटों के लिए भी मणिपुर जाने का समय नहीं मिला और न ही उन्होंने इसकी इच्छा जताई।

लोको पायलट को लेकर राजनीति, राहुल के दावे को रेल मंत्री ने किया खारिज

नईदिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोको पायलटों की कामकाजी परिस्थितियों से जुड़ी चिंता को संबोधित करने के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) का सहारा लिया, जिसे विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी ने भी उजागर किया है। मंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, लोको पायलट रेलवे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। चूंकि हमारे लोको पायलटों को हतोत्साहित करने के लिए विपक्ष द्वारा बहुत सारी गलत सूचनाएं और नाटकबाजी की जा रही है, इसलिए मैं चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं।

रेलमंत्री ने आगे लिखा कि लोको पायलटों के ड्यूटी घंटों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है। यात्राओं के बाद विश्राम सावधानीपूर्वक प्रदान किया जाता है। औसत ड्यूटी घंटे निर्धारित घंटों के भीतर बनाए रखे जाते हैं। इस वर्ष जून माह में औसत 8 घंटे से भी कम है। केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही यात्रा की अवधि निर्धारित घंटों से अधिक होती है। उन्होंने कहा कि पायलट लोको कैब से इंजन चलाते हैं। 2014 से पहले कैब की हालत बहुत ख़राब थी। 2014 के बाद से, एर्गोनोमिक सीटों के साथ कैब में सुधार किया गया है, और 7,000 से अधिक लोको कैब वातानुकूलित

हैं। नये लोकोमोटिव का निर्माण एसी कैब से किया जाता है।

रेल मंत्री ने कहा कि जब पायलट यात्रा पूरी करते हैं, तो मुख्यालय से बाहर होने पर वे आराम के लिए रनिंग रूम में आते हैं। 2014 से पहले रनिंग रूम की हालत बहुत ख़राब थी। लगभग सभी (558) रनिंग रूम अब वातानुकूलित हैं। कई रनिंग रूम में फुट मसाजर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। संयोगवश, कांग्रेस ने लोको पायलटों की कामकाजी परिस्थितियों को समझे बिना इसकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, बड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई और 34,000 रनिंग स्टाफ की भर्ती की गई है। वर्तमान में 18,000 रनिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री ने कहा, फर्जी खबरों से रेलवे परिवार को हतोत्साहित करने का प्रयास विफल होगा। पूरा रेल परिवार हमारे देश की सेवा में एकजुट है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को लोको पायलट से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा कि 'इंडिया' गठबंधन उनके अधिकारों और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए संसद में आवाज उठाएगा।

कठुआ आतंकी हमलों के लिए भाजपा जिम्मेदार: उमर

श्रीनगर। कठुआ आतंकी हमले पर जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे (बीजेपी) दावा कर रहे थे कि पूरा आतंकवाद अनुच्छेद 370 से जुड़ा है और इसके हटने के बाद यहां शांति कायम होगी...हमने लगातार कहा कि अनुच्छेद 370 का उग्रवाद से कोई लेना-देना नहीं है और अगर इसे हटा भी दिया जाए तो उग्रवाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे (भाजपा) अज्ञानी हैं। जब हम सत्ता में थे, तो हमें दोषी ठहराया जाता था ऐसे हमले तो आज, इन हमलों के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है...पहले भी हवाई हमले किए गए लेकिन क्या हमले नहीं रुके? अगर वे आश्वस्त कर सकते हैं कि हवाई हमले करके वे पूरे जम्मू-कश्मीर को मुक्त

करा सकते हैं उग्रवाद से, तो हम सुनने को तैयार हैं।

कठुआ में भारतीय सेना के काफिले पर आतंकवादियों के हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया था। बीते दिन उन्होंने कहा था कि कहा कि सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है। ये ग़लत है। दुनिया का कोई देश आतंकवाद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये आतंकवाद उन्हें(पाकिस्तान) बर्बाद कर देगा। जब आतंकवाद बंद होगा तब बातचीत शुरू होगी। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। उन्हें इस बारे में सख़्त कदम उठाने चाहिए। अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि कहीं भारत के सब्र का बांध टूट न जाए और लड़ाई हो।

खेल
प्रमुख समाचार

कार्लोस अल्काराज ने क्वार्टर फाइनल में टॉमी पॉल को हराया

लंदन। गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने अमेरिकी टॉमी पॉल की चुनौती को पार करते हुए विंबलडन 2024 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेनिश खिलाड़ी ने कोर्ट 1 पर कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 12वीं वरीयता प्राप्त पॉल को 5-7, 6-4, 6-2, 6-2 से हराया।

पॉल ने मैच की शानदार शुरुआत की और अल्काराज की सर्विस तोड़कर पहला सेट 7-5 से अपने नाम कर लिया। हालांकि, 21 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने जल्द ही वापसी की और दूसरा सेट 6-4 से जीतकर मैच को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद, अल्काराज ने खेल पर नियंत्रण पाया और तीसरे सेट में पॉल की सर्विस तोड़कर 6-2 से जीत हासिल की। मौजूदा चैंपियन ने चौथे सेट में भी अपना दबदबा बनाए रखा और उसी स्कोरलाइन से सेट जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी का अब सेमीफाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव से मुकाबला होगा, जो पिछले वर्ष के विंबलडन सेमीफाइनल का रिपीट देखने को मिलेगा, जहां अल्काराज ने उन्हें हराकर खिताब जीता था। पांचवीं वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने पांच सेटों के रोमांचक क्वार्टरफाइनल मुकाबले में दुनिया के मौजूदा नंबर एक खिलाड़ी इटली के जैनिक सिनर को 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 2-6, 6-3 से हराया। मेदवेदेव के खिलाफ अपने सेमीफाइनल मैच को लेकर अल्काराज ने कहा, 'वह वास्तव में एक महान खिलाड़ी हैं। यह पिछले साल जैसा ही सेमीफाइनल है। उम्मीद है कि मुझे वही परिणाम मिलेगा।' पॉल, जो अपना पहला विंबलडन क्वार्टरफाइनल खेल रहे थे, अपने प्रदर्शन पर गर्व कर सकते हैं। अमेरिकी खिलाड़ी ने ग्रास-कोर्ट सीजन में शानदार प्रदर्शन किया, क्वींस क्लब चैंपियनशिप जीती और विंबलडन में अच्छा प्रदर्शन किया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

मुनाफावसूली के कारण सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा टूटा

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को बड़े स्तर पर मुनाफावसूली के कारण बिकवाली के दबाव में बिखर गए और रिकॉर्ड हाई से नीचे आ गए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 129.72 अंक बढ़कर 80,481.36 के नए ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया। हालांकि, सूचकांक जल्द ही 915.88 अंक या 1.13 प्रतिशत गिरकर 79,435.76 पर कारोबार कर रहा था। अंत में यह 426.87 अंक या 0.53 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,924.77 अंक पर बंद हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में रिकॉर्ड 24,461.05 पर पहुंच गया, लेकिन इंट्रा-डे में 291.4 अंक या 1.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ इसका लाभ कम होकर 24,141.80 पर आ गया। अंत में यह 108.75 अंक या 0.45 प्रतिशत गिरकर 24,324.45 पर बंद हुआ।

आज जारी होंगे टीसीएस की पहली तिमाही के नतीजे

नईदिल्ली। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) गुरुवार, 11 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे पेश करेगी। विश्लेषकों के अनुसार, बिजनेस में सुधार और खरीदारी बढ़ने की संभावना को देखते हुए कंपनी के पहली तिमाही के नतीजों में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। हालांकि, वेतन बढ़ने से मुनाफे पर असर पड़ेगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के जून तिमाही के नतीजों में शुद्ध मुनाफा 11,771-12,140 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल की पहली तिमाही के 11,074 करोड़ रुपये से 6-9 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, तिमाही दर तिमाही इसमें 3-5 प्रतिशत की कमी हो सकती है।

ग्लोबल लेवल पर गोल्ड ईटीएफ में दूसरे महीने भी दिखा दम

नईदिल्ली। गोल्ड के लिए पिछला महीना उतार-चढ़ाव भरा रहा रहा। मई में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार दोनों में कीमतें जून 2024 के दौरान कमोबेश स्थिर रहीं। यूएस डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में तेजी के बावजूद सोने का रेंज -बाउंड रहना काफी मायने रखता है। आम तौर पर ये दोनों फैक्टर यदि मजबूत होते हैं तो सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ता है। जानकारों के अनुसार लगातार दूसरे महीने ग्लोबल लेवल पर गोल्ड ईटीएफ में बढ़े निवेश ने सोने की कीमतों को संभालने यानी रेंज बाउंड रखने में मदद की। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जून में एशिया और यूरोप से निकली खरीदारी ने उत्तरी अमेरिका से हुई निकासी को पीछे छोड़ दिया। दो महीने के लगातार इनफ्लो के चलते इस कैलेंडर ईयर की पहली छमाही के दौरान आउटफ्लो घटकर 6.7 बिलियन डॉलर (120 टन) रह गया।

एमक्योर फार्मा के आईपीओ की बाजार में धमाकेदार एंट्री

नईदिल्ली। एमक्योर फार्मास्युटिकल्स के शेयर की 10 जुलाई को शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत हुई। एनएसई और बीएसई पर एमक्योर फार्मा के शेयर का भाव 1,325.05 रुपये प्रति शेयर पर खुला, जो इश्यू प्राइस रू.1,008 से 31.45% अधिक है। बाजार विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि एमक्योर फार्मास्युटिकल्स के शेयर का भाव रू.1,370 से रू.1,390 प्रति शेयर के बीच खुलेगा। एमक्योर फार्मा आईपीओ लिस्टिंग के कुछ देर बाद शेयरों में तेजी देखने को मिली। सुबह 11 बजे करीब, कंपनी के शेयर 34.90 फीसदी के उछाल के साथ 1,360.30 के लेवल पर कारोबार करते दिखे। एमक्योर फार्मा का आईपीओ के सभी हिस्से बोली प्रक्रिया के तीसरे दिन ओवरसब्सक्राइब हो गए, जिसमें गैर-संस्थागत निवेशकों ने बढ़त बनाई। आंकड़ों के अनुसार, एमक्योर फार्मास्युटिकल्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस 67.87 गुना रहा।

आगामी पांच वर्षों में भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण हो सकता है दोगुना

(गतांक से आगे...)

प्रह्लाद सबनानी

भारत के नागरिकों की जेब में सीधे पैसे डालने के बजाय सामाजिक आधारभूत संरचना खड़ी करने में सरकार ने नागरिकों की भरपूर मदद की है, जैसे 3 करोड़ से अधिक मकान बनाकर गरीब वर्ग को उपलब्ध कराए गए हैं, ग्रामीण इलाकों सहित घरों में पानी उपलब्ध कराया गया है, 95 प्रतिशत से अधिक गावों में बिजली उपलब्ध कराई गई है, लगभग सभी घरों में गैस उपलब्ध कराई गई है, सड़क मार्ग विकसित किए गए हैं, गांवों में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, आदि।

भारत में उत्पादों के निर्माण में आधारभूत संरचना से सबंधित लागत बहुत अधिक है। इस पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14 प्रतिशत भाग खर्च हो जाता है, इससे उत्पादों की लागत तुलनात्मक रूप से बहुत बढ़ जाती है। हालांकि भारत के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए बहुत काम हुआ है। नए नए रोड बने हैं, रेल्वे का विकास हुआ है (रेल्वे का लगभग 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है), पोर्ट का विकास हो रहा है, नए एयर पोर्ट का निर्माण हुआ है, परंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष हैं। वर्ष 2015 ने भारत में मालगड़ियां औसतन लगभग 20 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलती थीं। अब वह औसतन लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और आगे आने वाले 5 वर्षों में यह और आगे बढ़कर औसतन लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगेगी। इससे सबसे बड़ा लाभ उद्योग जगत को हुआ है।

पिछले कई वर्षों से विनिर्माण क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी लगातार कम होती रही थे अथवा स्थिर हो गई थी।

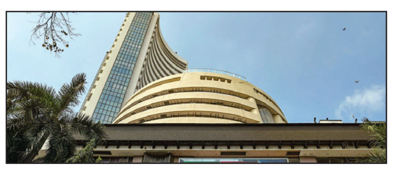

परंतु, अब यह स्थिति भी बदलती जा रही है और आने वाले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ने जा रही है। इसके परिणाम कई क्षेत्रों जैसे सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल्वे, फार्मा, औटोमोबाइल, ड्रोन निर्माण, सेमी कंडक्टर, फूड प्रासेसिंग, एयरो स्पेस, आदि में दिखाई भी देने लगे हैं।

भारत शेयर बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से विश्व में आज अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर है। तीसरे स्थान पर शीघ्र ही आ सकता है। आगामी 10 वर्षों में बहुत सम्भव है कि भारत दूसरे स्थान पर भी आ जाए क्योंकि चीन और जापान के आर्थिक क्षेत्र में जिस प्रकार की समस्याएं दिखाई देने लगी हैं, इससे अमेरिका के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आ सकता है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से विश्व में भारत तीसरे स्थान पर ही आ पाएगा। वर्तमान में भारत के शेयर बाजार का पूंजीकरण लगभग 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया है जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का ही हो पाया है।

आगे आने वाले लगभग 10 वर्षों में भारत में 10 करोड़ नागरिक गरीबी से निकलकर मध्यम वर्गीय परिवार बन सकते हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 45 करोड़ हो जाएगी। जबकि हाई नेटवर्थ नागरिकों की संख्या 50 लाख के आस पास ही है। इससे नागरिकों की खरीद क्षमता बढ़ेगी और उत्पादों की खपत भी बढ़ेगी। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने से गरीबी कम होती है। परंतु, महंगाई एवं विकास दर में संतुलन होना भी आवश्यक है। यदि मुद्रा स्फीति की दर बढ़ रही है तो यह गरीब वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित करती है अत: विकास दर को कम रखने का प्रयास किया जाता है ताकि महंगाई की दर को कम किया जा सके। इसी नियम को विश्व के कई देश लागू कर रहे हैं इसीलिए वैश्विक स्तर पर विकास दर भी कम हो रही है। परंतु भारत में महंगाई की दर को नियंत्रण में रखने में सफलता मिली है इसीलिए भारत की विकास दर भी 7 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। हालांकि यदि महंगाई को यदि और अधिक नियंत्रण में (लगभग 3 प्रतिशत) लाया जा सके तो भारत की आर्थिक विकास दर 8 से 9 प्रतिशत तक जा सकती है। भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की जोखिम दिखाई नहीं दे रही है परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में होने वाली समस्याओं के चलते ही हो सकती है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.